Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 05 30 मई, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से कोरोना का भंयकर कहर बनाम प्रशासनिक विफलता

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

यह गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा देश कोरोना महामारी पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या तथा जीवन की अंतिम सांसे लेने वालों की संख्या में विश्व में अग्रणी श्रेणी में आ चुका है। आज जनता जनार्धन के दिमाग में यह बात घर कर चुकी है कि देश का प्रशासन सामुहिक तौर से कोरोना महामारी व पीड़ित लोगो के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों दिखाई दे रहा है जबकि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के बाद यह निश्चित हो गया था कि राष्ट्र में इस महामारी की दूसरी भंयकर लहर आ सकती है। पूरी दुनिया में हमारे देश की जो छवि बन रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है भारत आपदा प्रबंधन में न केवल बुरी तरह नाकाम हुआ है बल्कि देश को चलाने वाले लोगों ने भारत के नागरिकों सहित पूरी दुनिया का भरोसा भी गंवा दिया है। देश के नेतृत्व ने अपनी छवि चमकाने के चक्कर में असल में देश की छवि के साथ ही खिलवाड की है

लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी वर्ग यह महसूस करता है कि राजनैतिक ऊंचाईयों को छूने की महत्वाकांक्षा के कारणवश आज के शासक दल को जनता की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है और राज्य की ताकत तथा राष्ट्रीय सता को आम जनता की पीड़ा को और अधिक बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। आक्सीजन व जीवन रक्षक औषधियां कोरोना पीड़ितों व गरीब जनता तक पहुंचाने की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है लेकिन जीने के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हुये पुलिस की मार्फत मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। 15 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा पोस्टर चिपकाकर केंद्रीय सरकार की कोरोना के संबंध में की गई कारगुजारी का विरोध करने के तथाकथित आरोप लगाकर 24 निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी में जेलों मे केवल 10,000 की क्षमता है लेकिन 30 अप्रैल तक वहां पर 20,500 कैदी जेलों में बंद है। यही हालात राष्ट्र की अन्य कारागारों की है। आज राष्ट्र का हर वर्ग कोरोना महामारी से पीड़ाग्रस्त व शोकग्रस्त होता जा रहा है जोकि मानव अधिकारों का सरेआम उल्लंघन है।

इस समय राष्ट्र का 2 तिहाई हिस्सा महामारी की चपेट में आ चुका है और 533 जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कोरोना से संक्रमित है और लगभग 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया है जो कि शून्य के बराबर है। भारत में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या करीब डेढ़ करोड़ के पास पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर पहली के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था शून्य के बराबर है और गांवों की स्थिति तो अभी भांप ही नहीं सकते हैं। राष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार इसलिए नहीं थम रही क्योंकि अब कोरोना वायरस शहरों से गांवों में फैल रहा है। इस समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश आदि 13 प्रमुख राज्य हैं, जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के नए मामले इन सभी राज्यों में 50 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से हैं। पूरे देश में साढ़े 6 लाख गांव हैं, और इनमें लगभग 90 करोड़ लोग रहते हैं। हरियाणा के किसी भी गांव में जाकर देख लें पूरे गांव झोलाछाप से दवाइयां ले रहे हैं और रोज किसी ना किसी अपने की लाश कंधों पर ढोकर श्मशान पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार केरल और बंगाल में 75 प्रतिशत से अधिक कोरोना पीड़ित रोगी ग्रामीण इलाकों से हैं।

हरियाणा के रोहतक, हिसार, झज्जर आदि जिलों के अनेक गांवों में 20 से 25 व्यक्ति प्रति गांव कोरोना का शिकार हो चुके हैं केवल टिटोली गांव में 60 से अधिक महामारी से जान गवां चुके हैं और एक व्यक्ति के दो युवा बेटे इस महामारी का शिकार हो चुके हैं जिनको बचाने के लिये 35000 हजार रुपये का वैक्सीन भी लगवाना पड़ा। रोहतक में 230 में से 57 गांव पूरी तरह कोरोना संक्रमण की चपेट में है। यही हालात प्रदेश के अन्य जिलों की है अगर यह महामारी गांवों में छोटी उमर के बच्चों तक फैल गई तो स्थिति और अधिक भयानक हो सकती है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, बठिढ़ा, जांलधर आदि जिलों में स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है। एक सर्वे के अनुसार पंजाब के पटियाला में 10 दिन में 50 मौते हुई है। लेकिन प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं व किसी भी एन.जी.ओ. द्वारा इस घातक महामारी के नियंत्रण के लिये गांवों में आवश्यक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन, पैरासिटामोल, सैनाटाईजर व मास्क तक भी उपलब्ध नहीं है।

स्थिति यह है कि कोरोना से अधिक प्रभावित गांवों में पीड़ितों का संस्कार करने के लिये इंधन भी कम पड़ने लगा है और शमशान घाट में एक समय में कई शवों का संस्कार किया जा रहा है और शव का संस्कार करने के लिये इंतजार करना पड़ता है। मुस्लिम व ईसाई समुदाय भी इस शर्मनाक स्थिति से जूझ रहा है

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

क्योंकि कब्रिस्तानों व गिरजा घरों में शवों के दफन के लिये जगह कम पड़ रही है। यूपी व बिहार में तो कोरोना पीड़ितों के शवों को नदियों व नहरों में फैंका जा रहा है। शवों के संस्कार के लिये 16 हजार से 20 हजार तक वसूल किये जा रहे है जिससे गरीब व्यक्ति शव को पानी में बहाने पर मजबूर है। बिहार के बक्सर जिले व यूपी में सैंकड़ो शव गंगा में तैरते हुये मिल चुके है जो कि सरकार व प्रशासन की नैतिकता व संवेदनशीलता का जनाजा है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना से जान गंवा रहे लोगों की सही संख्या की जानकारी देने में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ो व शमशान घरों से प्राप्त आंकड़ों में भारी अन्तर है। इस समय गांवों में कोरोना का मृत्यु दर 2.86 प्रतिशत है जबकि शहरों का 1.73 प्रतिशत है जो कि दोगुना है। पिछले माह बेगलुरू में इसी तरह क आंकड़े जारी हुये जहां 1422 की तुलना में 3104 मौते कोविड प्रोटोकोल के साथ हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से 3 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं जो कि विश्व में तीसरे नम्बर पर है। कोरोना महामारी के पीड़ितों के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा जारी आंकड़े भी संदेहास्पद हैं। गत वर्ष एक मार्च से 10 मई 2020 तक 71 दिन में गुजरात सरकार द्वारा कोरोना के 58068 मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए गए। इस साल इतने ही समय में गुजरात सरकार द्वारा 123873 मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए गए जोकि गत वर्ष से 65805 अधिक हैं। कोरोना पीड़ितों की यह संख्या सरकार द्वारा अधिकारिक तौर से प्रमाणिक है जोकि निश्चित रूप से प्राकृतिक बढ़ोतरी नहीं है। जबकि सरकार का दावा है कि कोरोना से केवल 4218 मौत हुई हैं जोकि पीड़ितों की बाकी संख्या पर संदेह उत्पन्न करती है। 12 अप्रैल 2021 को देश में कोरोना वैक्सीन की डोज 4265157 से कम होकर अगले छह रोज तक 20 लाख से भी कम हो गई। अखबार के मुताबिक यह स्पष्ट तौर से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन की अपर्याप्त सप्लाई का सुबूत है, जबकि सरकार व प्रशासन इसके विपरीत वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति का प्रसार व दावा कर रहा है। 9 मई 2021 को इकोनॉमिक टाईम्स द्वारा जारी ग्राफ में भी दर्शाया गया है कि देश में प्रतिदिन दी जा रही कोरोना वैक्सीन की दर लगातार घट रही है।

हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे आम नागरिक को तो पूछता ही कौन है साधन सम्पन्न व उच्च वर्ग के लोग भी स्वास्थ्य सुविधाओं, ईलाज की कमी से मर रहे है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज की आक्सीजन न मिलने से मृत्यु हो गई। अप्रैल मास में विदेशमंत्री श्री जय शंकर द्वारा फोन करने के बावजूद मेदांता हस्पताल गुरूग्राम में दाखिल न किये जाने के कारण भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत), नाईजीरियां के पूर्व राजदूत श्री अशोक अमरोही व पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री लक्ष्मण दास की सरकारी अन्देखी से मृत्यु हो गई।

स्वास्थ्य तंत्र के हाल पर अगर बात की जाए तो बस भगवान के हवाले ही देश है। हस्पतालों में फिलहाल सारे आई.सी.यू. और कोविड–19 आई.सी.यू. पूरी तरह भरे हुए हैं। मरीज आक्सीजन और वेंटीलेटर की आस में ही इस दुनिया से जा रहे हैं। गरीब मरीज जमीन पर लेटकर मौत की सांसे गिन रहे हैं बैडों की कमी के कारण एक बैड पर दो–दो मरीज भी गुजारा कर रहे हैं और कोरोना पीड़ितो के शवो को सरकारी अव्यवस्था के कारण ऑटोरिक्शा, रेहड़ी पर लादकर व सिर पर उठाकर ले जाया जा रहा है और श्मशान घाट में जगह न मिलने के कारण गंगा में बहा दिया जाता है।

वैक्सीन मैत्री के नाम पर केन्द्र सरकार ने अपनी छवि चमकाने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर दिया। जो डोज पहले भारत के लोगों को लगनी चाहिए वो डोज विदेशों की धरती पर उतारी जाने लगी। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने अब तक 90 देशों को करीब 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन दी हैं। इनमें से 54 फीसदी का व्यापार के तहत निर्यात हुआ है, 16 फीसदी दान में दिए गए हैं और बाकी के 30 प्रतिशत का निर्यात कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हुआ है। 70 प्रतिशत दान पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को दिए गए हैं। ये कुल निर्यात का एक–तिहाई हैं। भारत ने इन देशों को करीब 1 करोड़ 80 लाख टीके दिए हैं। वैक्सीन के ज्यादातर टीके अफरीकी देशों, मोरक्को, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ब्राजील आदि को व्यापारिक निर्यात के तहत भेजे गए।

भारत में हर दिन जिन लोगों को टीके दिए जाते हैं उनकी संख्या करीब 20 या 25 लाख होती है और अगर भारत की पूरी आबादी को अगले आठ महीने के दौरान टीके लगाने हैं तो हर दिन लगाए जाने वाले टीकों की संख्या 70 से 80 लाख या एक करोड़ होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बड़े ढांचे की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की जरूरत होगी। अप्रैल की शुरुआत में देखने को मिला कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां टीके लगाए जा रहे थे वहां भी पहली और दूसरी खुराक के लिए समय देने में दिक्कतें आ रहीं थीं। कुछ केंद्रों पर वैक्सीन ही नहीं थीं। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन का भार राज्यों पर डालकर और केंद्र और राज्य सरकारों के लिये वैक्सीन के अलग–अलग दाम तय कर स्थिति को और बिगाड़ दिया। आम बजट में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और नियंत्रण के मद्देनजर ऐलान किया था कि कोरोना की वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल अगर किया होता तो देश के 100 करोड़ लोगों को

वैक्सीन लग चुकी होती। इसी प्रकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि एक नया आधुनिक संसद भवन बनाने पर खर्च किया जा रहा है। अगर इस पैसे को आम आदमी के हित के लिए खर्च किया जाए तो इससे 100 दिन तक 40 करोड़ बच्चों के लिए एक समय के भोजन की व्यवस्था हो सकती है जोकि समय की जरूरत है क्योंकि वर्ष 2020 के सर्वे के अनुसार भारत में भुखमरी का इंडेक्स 107 देशों में 94वें स्थान पर है।

फरवरी के आखिर में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव आ गए। इन राज्यों में 18 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है। सत्तादल व दूसरे दलों के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां में धुंआधार प्रचार शुरू कर दिया और एक साथ लाखों लोगों को रैलियों में बुलाया गया। आज पश्चिम बंगाल में हर चौथा आदमी संक्रमित है और सेहत पर सत्ता हावी हो गई है। इसलिये देश के वे सभी राजनैतिक दल इसके लिये जिम्मेवादर है, जिन्होंने भीड जुटाई थी। जो समय व पैसा देश के प्रधानमंत्री को देश को इस महामारी से निपटने से देश को तैयार करने में लगाना था वो चुनाव में बहा दिया और देश बर्बादी के कगार पर आ गया। करीब–करीब उसी दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच खेले गए। उसके बाद कुंभ मेला शुरू हो गया जिसमें लाखों लोग पहुंचे। सरकार की ओर से बरती गई इस घोर लापरवाही से भी हालात ज्यादा खराब हुये है। वैज्ञानिकों का मानना है चुनाव, धार्मिक मेले और इस तरह के दूसरे आयोजन और महामारी से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही दूसरी लहर के मुख्य कारण हैं।

कोरोना ने देश के कुछेक लोगों के चरित्र को भी उजागर कर दिया है। कालाबाजारी ने हर सीमा लांघ दी और उनसे निपटने में तंत्र भी फेल रहा। कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से फैल रही है उसी तेजी से आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ी। हालात इस कदर बदहाल है कि प्रशासन इस ओर मूकदर्शक की भांति तमाशा देख रहा है। पान मसाला, फल, मेवा तथा दाल–चावल तक कालाबाजारी के शिकार हो गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क व अन्य आवश्यक वस्तुएं भी बीते सप्ताह की तुलना में डेढ़ से दो गुनी अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। कई दवाईयां बाजार से गायब हो गई हैं तो कुछ दोगुने दामों पर बेची जा रही है। पल्स ऑक्सोमीटर तक नहीं मिल रहा है। खाद्यान्न के साथ दलहन–तिलहन की निरंतर बढ़ रही महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है।

कोरोना महामारी की रोकथाम हेतू प्रथम सुरक्षा पंक्ति में लगे हुये पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी आदि भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे है। अप्रैल के अंत से तो लगातार औसतन 100 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो रहे है। अब तक एक दर्जन एसपीओ व पुलिस वालो की कोरोना से मौत हो चुकी है जिसमें 2 डीएसपी शामिल है। इसके साथ ही हरियाणा के हस्पतालों में काम करने वाली 600 नर्सें व एन.एच.आर.एम. के करीब 1000 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके है। भारतीय चिकित्सक संघ (आई.एम.ए) के अनुसार कोविड़–19 की पहली लहर में 748 डाक्टरों की मौत हुई थी जबकि दूसरी लहर में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आकर 1017 डाक्टरों की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य स्टाफ इससे अलग है।

महामारी का सुरक्षा बलों पर भी प्रभाव बढ़ रहा है। सेना के जवान भी इससे संक्रमित हैं। राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुये सुरक्षाबल भी कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं अभी तक 5134 सुरक्षा सैनिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरा है। कोविड–19 की वजह से भारतीय सेना को अपने ट्रेनिंग सिस्टम में कई तरह के बदलाव तो करने ही पड़ रहे हैं साथ ही इसकी वजह से सेना को नए अफसर और नए जवान मिलने में भी देरी होगी। कोरोना का कहर अगर लंबे वक्त तक चला तो सेना की दिक्कत भी बढ़ सकती है। सेना में प्रत्येक स्तर पर नए रिक्रूटमेंट और प्रशिक्षण केंद्र बंद हैं। कोरोना से निपटने के लिए देश के साथ सेना कंधे से कंधे मिलाए चल रही है लेकिन खुद उसके जवान कोरोना से बदहाल हैं लेकिन महामारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुडा हुआ मसला है।

बिगडी हुई परिस्थितियों में देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा कि कोविड–19 संकट के चलते देश में बेरोजगारी की दर तीन मई को सप्ताह के दौरान बढ़कर 27.11 प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 29.22 प्रतिशत रही, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 26.69 प्रतिशत थी। अब अगर बीमारी से बच भी गए तो देश के लाखों लोगों को ये बेरोजगारी ले डूबेगी। एक निजी शोध फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे में आंकड़े सामने आए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में भारत में लगभग 7 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं।

कोरोना के लगातार बढ़ते हुये प्रकोप से माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और केन्द्रीय सरकार को कई बार आवश्यक निर्देश देकर कहा कि हम लगातार जान गंवा रहे निर्दोश/असहाय लोगों की दुर्दशा पर आंखे बंद नहीं कर सकते और सरकार को कोरोना महामारी को रोकने के लिये गंभीर कदम उठाने चाहिए लेकिन स्थिति में अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। देश को कोरोना की तीसरी लहर का दंश न झेलना पड़े इसके लिए पहला और प्रभावी कदम होना चाहिए जो 35 हजार करोड रुपये की बात श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी उसका एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन बनाने की तेज रफ्तार और देश के हर व्यक्ति

को सरकार की तरफ से मुफ्त टीका लगवाने में लगना चाहिए। वैक्सीन को बनाने का तरीका देश की हर संभव वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ शेयर करके, फील्ड अस्पताल बनवाकर और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाकर देश के लोगों को लगाने की पहल ही देश को इस भयावह संकट से बाहर निकाल सकती है।

कोरोना महामारी के फैलाव के बारे में केन्द्रिय सरकार के साथ–साथ राज्यों व बड़े निजी हस्पतालो की जबाबदेही निश्चित की जानी चाहिए क्योंकि यह संकट लोगों के जीने के अधिकार से जुड़ा है। निजी हस्पतालो को जीवन रक्षक आवश्यक औषधियों व सामान के ईलावा अपने हस्पतालों में आक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये आवश्यक निर्देश दिये जायें ताकि मासूम लोगो की जिन्दगी से खिलवाड़ ना हो। निजी हस्पतालो को पब्लिक हित में सस्ते दर पर सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जाती है इसलिये इनके लिये लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जानी जरूरी हैं। कोरोना के साथ–साथ नई बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस–ब्लैक फंगस के मामले भी उजागर हो रहे हैं। भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का 1.29 प्रतिशत है जोकि बंगलादेश व नेपाल से भी कम है, इसलिए स्वास्थ्य तंत्र को समुचित तौर से पुर्नगठित करने व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को महामारी से पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता एवं नम्रता बरतनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खौफनाक महामारी की तीव्रता को नियंत्रण करने के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य संगठनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को समुचित तौर से प्रभावी व सुविधा पूर्ण बनाना आवश्यक है जिसके लिये विभिन्न एन.जी.ओ., विद्यार्थियों, एन.सी.सी. तथा समाज सेवी संगठनो से तालमेल बनाकर लोगों को जागरूक किया जाये। इसके साथ ही सरकार को फजूल की ब्यानबाजी छोड़कर संकट की इस घड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर टैंस्टिग, वैक्सीनेशन शुरू करके देहात में ही सार्वजनिक चौपालों, स्कूलों आदि में आईसोलेसन केन्द्र बनाकर पीड़ितों के उचित उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवायें निभा रहे स्टाफ की अस्थाई सेवाओं को स्थाई किया जाये और उनके वेतन व भत्ते बढ़ाये जाये ताकि वह मरीजो की श्रद्धाभावना से सेहत सेवायें मुहैया करवाये।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

असहाय परिवारों को मिले मदद

– शम्भू भदरा

योगेश कुमार सोनी कोरोना की वजह से मानव जीवन भारी संकट में आ चुका है, लेकिन अब उन परिवारों की परेशानी बहुत बढ़ गई जिनके घरों की अकेले व्यक्ति के आधार पर जीविका चल रही थी। सरकारें अपने–अपने स्तर पर मदद करने की घोषणाएं तो कर रही हैं, लेकिन अभी धरातल पर सब शून्य है। मध्यम व गरीब वर्ग के परिवारों का जीवन कठिनाई की ओर इसलिए चला गया चूंकि इनके पास बैकअप के रूप में किसी भी प्रकार की धनराशि व संपत्ति नहीं होती। इनमें से बहुत से लोग तो किराए पर भी रहते हैं और ऐसे लोगों को जीवन–यापन करना बहुत बेहद मुश्किल हो रहा है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना से देश में अब तक ढाई करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब पौने तीन लाख लोगों की मौत हो चुकी है और यह वो आंकड़ा है जो सरकार ने बताया है। यदि सच्चाई पर जाएं तो निश्चित तौर यह दोगुना होगा। यदि इन आंकड़ों का भी वर्गीकरण करें तो मरने वाले 68 प्रतिशत गरीब व मध्यमवर्गीय लोग हैं।

बीते दिनों मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना से मरने वालों के परिजनों की मदद करने की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि 'मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने माता–पिता को कोरोना से खो दिया है। मैं उनका दर्द समझता हूं। इसके अलावा जिन बुजुर्गों ने अपने घर के कमाऊ युवाओं को खो दिया है, उन्हें भी सरकार मदद देगी। दिल्ली सरकार ऐसे बुजुर्गों को आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।' सवाल व स्थिति अपनी जगह अडिग है, क्योंकि पीड़ित परिवारों को मदद कब और कैसे मिलेगी इसका अभी कोई अता–पता नही हैं? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोज कमाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, मृतक के घरवालों को मकान मालिकों ने किराए का पैसा न मिलने पर भगाना शुरू कर दिया व राशन वालों ने उधार देना बंद कर दिया। हालात बद से बदतर होने लगे हैं। ऐसे लोग सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो खाना मिल जाता है उस ही पर आश्रित हो गए। जिसके परिवार में बूढ़े मां–बाप, पत्नी और बच्चे हैं और उनका कमाने वाला चला गया उन परिवारों की स्थिति बेहद दननीय होती जा रही है। ऐसे स्थिति में बूढ़े मां–बाप कमा नहीं सकते। पत्नी छोटे बच्चों को छोड़कर जा नहीं सकती। यदि कुछ महिलाएं जा भी सकती हैं तो लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नही मिल रहा।

ऐसे लोगों के लिए सरकार को बेहद गंभीरता से सोचने की जरूरत है, चूंकि जो कोरोना से मर गया वहां तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसे लोग मात्र भूख से ही मर जाएंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। यहां अन्य मामलों की तरह घोषणाओं को लटकाते हुए काम नहीं चलेगा, चूंकि इस बार मामला मानव जीवन पर संकट और बुनियादी जरूरत का है। यदि लोग भूख से मरने लगे तो यहां सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत होने लगी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि जिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिला और वह बिना इलाज के ही मर गए, उन लोगों को सरकार अपने आंकड़े में नहीं गिन रही। इस दिशा में एक कमेटी गठित करके जांच के आधार ऐसे परिवारों को भी मदद देने की जरूरत है। यहां केन्द्र व राज्य सरकारों को बड़े एक्शन ऑफ प्लान की आवश्कता है। सवाल यह है कि ऐसे में सरकारें अपनी राजनीति चमकाने व उपस्थिति दर्ज कराने के चक्कर में जनता को निशाना न बना लें।

उदाहरण के तौर पर यदि हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां का वासी केन्द्र व राज्य सरकार के आपसी मतभेद की भेंट चढ़ जाता है। हर मामले पर केजरीवाल कहते हैं कि हम केंद्र सरकार से कुछ मांगते हैं तो वह देती नहीं। केजरीवाल ने अपने स्तर कोरोना से पीड़ित परिवारों की मदद का जो ऐलान किया है तो वह उसको जल्द से जल्द पूरा करें। यदि वो अन्य घोषणाओं की तरह इसमें राजनीति कर गए तो जनता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। चूंकि इस बार जरूरत किसी योजना के लाभ से नहीं जुड़ी अब तो मामला भूख से मरने का हो गया। हालात बेचैन करने वाले बन चुके हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन में केजरीवाल ने मकान मालिकों से किराया न लेने की अपील की थी, लेकिन उसके लिए कोई कानूनी खाका तैयार नहीं किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी मकान मालिक ने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने तो किराएदारों का सामान घर से बाहर फेंक दिया था। ऐसे मामलों में पुलिस भी कोई सहायता नहीं कर पाई थी। केजरीवाल या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मदद की घोषणाओं के बाद जरूरतमंद टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार हमें बचा लेगी, इसलिए तुरंत प्रभाव के साथ पूरे देश में इस मामले को लेकर एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। इस बार केंद्र सरकार का स्वास्थ्य बजट 94,452 करोड़ था, लेकिन कोरोना संकट के चलते बढ़ाकर 2,23,846 करोड कर दिया। इस बजट में 35000 करोड़ की वैक्सीन भी शामिल है, लेकिन यहां अहसहाय परिवारों की मदद के लिए थोड़ा सा और बजट बढ़ाया जाए।

अपने–अपने देश की जनता के लिए आर्थिक मामलों पर विश्वस्तरीय चर्चा करें, तो अमेरिका ने पिछले वर्ष कोरोना से मरने वालों के परिजनों व लॉकडाउन की वजह से 17.5 करोड़ डॉलर के पैकेज के द्वारा मदद की थी व इस वर्ष भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 139 राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत हर अमेरिकी को खाते में करीब एक लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब व अन्य तमाम देशों ने अपने नागरिकों को आर्थिक मदद करके उन्हें संकट में नहीं आने दिया। हमारे देश में संदर्भ में चर्चा करें तो अधिक जनसंख्या का होना हमें पिछड़ा बनाता है। पूरी दुनिया में लगभग साढ़े सात सौ करोड़ हैं लोग हैं जिनमें से एक तिहाई हमारे देश और चीन में रहते हैं। अधिक जनसंख्या में एक समान किसी भी चीज का लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वैश्विक आपदा से निपटने के लिए काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में दलालों का होना भी हमे उभरने नहीं देता। गांव में शौचालयों की योजना में एक घर में एक बजाय तीन शौचालय बताकर घपला किया। सर्वे करने वालों ने आधे पैसे स्वयं लिए व आधे लाभकारी को दिए। यह तो केवल एक योजना के घपले का उदाहरण है, लेकिन यहां केंद्र व राज्य सरकारों को स्वयं धरातल पर उतरकर काम करना होगा। यदि यह काम राज्य स्तर करना है तो उसके लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाए और तुरंत प्रभाव से आदेश दिया जाए और यदि यह केंद को अपने संरक्षण में करना है तो भी जल्द से जल्द खाका तैयार कर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जाए। (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

इजराइल-हमास के बीच हिंसा तत्काल रोके यूएन

– मंजू रानी

इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष का तत्काल अंत होना चाहिए। भारत ने इस हिंसा की निंदा की है। विश्व जब कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में दो मुल्कों का आपस में खून बहाना कहीं से भी उचित नहीं है। इजराइल व फिलीस्तीन के बीच 1967 से ही दुश्मनी है। यरूशलम में इस्लाम, ईसाई व यहूदी तीनों की पवित्र धर्म स्थली है। पूर्वी यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद है। यह मक्का व मदीना के बाद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल है। समूचे यरूशलम पर इजराइल का कब्जा है। वह पूर्वी यरूशलम से मुस्लिम आबादी को खाली करना चाहता है। फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र

फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इजराइल पूर्वी यरूशलम से अपना दावा छोड़े। अभी रमजान के मौके पर इजराइल ने पूर्वी यरूशलम से मुस्लिम आबादी को खाली कराना शुरू किया, जिसका हमास विरोध कर रहा है। ताजा संघर्ष इसलिए है। इसके चलते इजराइल में यहूदी व अरब आबादी के बीच सांप्रदायिक हिंसा भी फैल गई है। हमास का गाजापट्टी पर कब्जा है।

इजराइल हमास को आतंकवादी गुट मानता है। अभी इजराइली सुरक्षा बल के खिलाफ हमास का विरोध मामूली झड़प से हिंसक जंग में तब्दील हो रहा है। एक सप्ताह के अंदर सौ से अधिक बेकसूर मारे गए हैं। दोनों ही मुल्क में महज लाखों में आबादी है, फिर भी दोनों एक–दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। चिंता की बात है कि इजराइल व फिलिस्तीन के बीच विवाद केवल दो मुल्कों का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह इस्लाम, यहूदी व ईसाई सभ्यता व मान्यता के बीच के टकराव की परिणति भी है। इजराइल वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स को अपना क्षेत्र बताता रहा है। मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल को हमेशा इस्लामिक कट्टरता के विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसमें फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश गोलबंद हो जाते हैं तो इजराइल की मदद को पश्चिमी देश आ जाते हैं। अभी ताजा संघर्ष के बाद जहां अमेरिका, जर्मनी आदि देश इजराइल के आत्मरक्षा पक्ष को सही मान रहे हैं, तो मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) फिलिस्तीन के साथ है। आईओसी के 57 देशों ने 16 मई को आपात बैठक बुलाई है।

ओआईसी के सदस्य तुर्की, सऊदी अरब व पाकिस्तान ने यूएन जाने का फैसला किया है। विश्व स्तर पर रूस व चीन अपरोक्ष रूप से फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े दिखेंगे। इसमें वैश्विक विभाजन साफ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इजराइल व हमास से खूनी संघर्ष बंद कर शांति की अपील की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस लड़ाई से दोनों देशों में कट्टरता बढ़ेगी। भारत ने यूएन में दो टूक कहा कि वह सभी तरह क हिंसक गतिविधियों की भर्त्सना करता है। भारत चाहता है कि हिंसा तत्काल बंद हो। एक भारतीय नागरिक की मौत पर भी भारत ने इजराइल से अपनी चिंता जाहिर की है। भारत ने सभी पक्षों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का पालन करने की भी अपील की जो कहता है कि पूर्वी यरूशलम समेत फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में इजरायल द्वारा 1967 से अन्य बस्तियों की स्थापना की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत घोर उल्लंघन है। इजराइल व फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करना चाहिए। 1948 में इजराइल की आजादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने–सामने आ चुके हैं, हालात 2008–09 या फिर 2014 जैसे नहीं हो, इसलिए यूएन को चाहिए कि इजराइल व हमास के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में तेजी से पहल करे।

घटती जैव विविधता को रोकना जलवायु परिवर्तन की तरह मानव सभ्यता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती

– डॉ. सुनील कुमार भारतीय वनसेवा,
यदु भारद्वाज भारतीय वनसेवा

जैव विविधता दिवस पर विशेष हर वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है जिसका उदेश्य लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करना और इस वर्ष जैव विविधता दिवस की थीम है 'वी आर पार्ट ऑफ साल्यूषन'। कोरोना महामारी ने ना केवल दुनिया के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर नाकारात्मक असर डाला है बल्कि इसके कारण विश्व भर में अभी तक लगभग 35 लाख लोगों की जान चली गई है कई बच्चे अनाथ हो गये हैंए कई परिवार पूरी तरह उजड़ गये हैं काफी लोग बेघर हो गये हैं। जैसे ही समाज ने यह महसूस करना शुरू किया कि हम पहली कोरोना की लहर से उबर चुके हैं दूसरी कोरोना लहर बड़े ही बलपूर्वक मानव सभ्यता पर कहर की तहत टूट पड़ी।

विभिन्न वैश्विक विषेषज्ञ यह मानते हैं कि जैव विविधता के नुकसान, जैव विविधता के आवासों का विखंडन, वनों के लगातार कटाई और मनुष्य का प्रा.तिक जैव विविधता में बढ़ते इन्टरफेस के कारण इस तरह के भयानक जुनोटिक रोग फल रहे हैं। इस घातक बीमारी से मानव सभ्यता को जो झटका लगा है उसने हमें प्रा.ति में अपनी स्थिति और भूमिका पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इस महामारी ने मनुष्य जाति को यह अहसास कराया है कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं हैं बल्कि इस अनंत प्रणाली के एक सक्रिय घटक हैं। हमारा अस्तित्व और कल्याण प्राकृतिक प्रणालियों के समांजस्यपूर्ण कामकाज पर निर्भर करता है। अभी तक प्रर्यावरण प्रबंधन पर पूरा विचार–विमर्श यह अहसास दिलाने पर केन्द्रित था कि कैसे उनकी प्रकृति को शोषण करने की

गतिविधियों ने पारिस्थितिक तन्त्र को नष्ट कर दिया है लेकिन इस दिषा में वर्ष 2020 को एक वाटर शैड वर्ष माना गया है कि कैसे मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाली जैविक प्रणालियों की रिकवरी में मदद करेगा।

आज प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा बता सकता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई, वायु प्रदूषण, पानी की कमी से होने वाली अकाल, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के विलुप्त होने की बढ़ती दर, जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रदार्थों का निपटान प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। लाइनर प्रोजेक्ट जैसे कि रेल और सड़कों नें वन्य जीवों के आवासों में .त्रिम विखंडन पैदा किया है जिसके फलस्वरूप मानव वन्यजीवों में संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय मुददों और वन्य जीवों और आवासों के विनाश के बारे में जागरूकता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है लेकिन इस दिशा में हमें काफी आगे बढ़ना बाकी है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम स्वयं जैव विविधता के नुकसान जैसी विकराल समस्या के समाधान खोजना शुरू करें। पर्यावरण से सबंधित अर्न्तराष्ट्रीय और सरकारें अकेले इस उददेश्य को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो ईकोकृसिस्टम की सेवाओं का उपयोग करता है उसे प्राकृतिक तन्त्र की नुकसान की भरपाई को कैसे पूरा करें इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पर्यावरण ऑडिट करना चाहिए जैसे कि कैसे हम पानी के दुप्रयोग को कम कर सकते हैं। इस तरह के पर्यावरण ऑडिट से रिसोर्स यूज एफिसिएंसी बढ़ेगी। इसी दिशा में दूसरा कदम यह भी हो सकता है जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में पॉलीथीन बैग का उपयोग करते समय इसके विकल्प की दिशा में भी सोच सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने आस–पास की दो कि.मी. की दूरी में होने वाली दैनिक क्रियाएं साइकिल के माध्यम से करें तो इससे ईंधन की खपत कम होगी मनुष्य स्वस्थ रहेगा तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। अतः समय आ गया है कि जब भी हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे होतें हैं तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें वास्तव में मुझे इसकी आवश्यकता है तथा कहीं इसके प्रयोग से पर्यावरण को कोई हानि तो नहीं होगी।

मनुष्य समाज को पेड़ों और वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वच्छ हवा और पानी जैसी अमुल्य सेवाओं के महत्व का अहसास होना चाहिए। एक औसत इंसान को 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो पेड़ों झीलों और महासागरों में मौजूद फाइटोप्लांकटन से आती है। इस ऑक्सीजन का आर्थिक मुल्यांकन करने पर हमें यह अहसास होना चाहिए कि इस निःशुल्क प्राकृतिक सेवा का भुगतान ना करके हम कितना पैसा बचा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी प्राकृति के आभारी होने के बजाए हम मानव जाति दिन प्रतिदिन होने वाले वनों की कटाई, वेटलैंड का नुकसान और जलवायु परिवर्तन फलस्वरूप बढ़ने वाले महासागरों के अवनिकरण के बारे में बहुत ही कम चिंतित नजर आती है। यह अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 50000 हेक्टेयर जंगलों की कटाई होती है या जलाए जाते हैं।

समय आ गया है कि लोग यह सोचें कि इन ईको सिस्टम से प्राप्त होने वाली विभिन्न सेवाओं का भुगतान हम कैसे करें। इसका भुगतान हम अपने और अपने आस–पास की दैनिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन करके कर सकते हैं उदाहरणस्वरूप अपने घरों और व्यवसायिक परिसरों में रेन वाटर हारवेस्टिंग संरचनाएं लगाएं अपने घर, कॉलोनी गांव व कस्बों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें और यह प्रण लें कि इन पेड़ पौधों की तीन से चार साल तक अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करेगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण जो लोग बहुमंजलीय इमारतों में रहते हैं वह यह सुनिश्चित करें कि उनके कम्पाउंड में कम से कम 33 प्रतिशत हरितवान हो। शहर के मास्टर प्लान बनाते हुए ग्रीन कोरीडोर को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह नागरिक भागीदारी और क्राउड फंडिंग द्वारा इस ग्रीन कोरीडोर को सफल बनाया जा सकता है। समय आ गया है शहरी क्षेत्र में समाज के सभी लोग खाली जमीन के पैच को पौधारोपण के लिए अपनाएं। इसके अलावा वन विभाग और बागवानी विभाग के सहयोग से इस तरह की योजना करें कि इस खाली पैच पर विभिन्न प्रजातियां जैसे कि छायादार पेड़, फलदार पेड़ और सजावटी पौधे लगायें। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लधुग्राम वन बनाएं जा सकते हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के धनाढय और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे ग्राम वनों को पांच वर्षों के लिए गोद ले सकते हैं और इन ग्राम वनों में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो ताकि हरित स्वयं सेवकों की एक फौज ग्रामीण स्तर पर तैयार हो सके। इसी तरह यह एक वैश्विक अनुमान है कि प्रतिदिन 25 लाख टन भोजन बर्बाद हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सघन कृर्षि जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइज का प्रयोग होता है उससे यह भोजन उत्पन्न होता है। समाज को ना केवल अपने खाने की आदते बदलनी चाहिए बल्कि समय आ गया है कि इन्टीग्रटेड फूड मैनेजमेंट को अपनाने का समय आ गया है ताकि हम फूड चेन में .त्रिम घटकों का उपयोग कम कर सकें। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जैव विविधता के नुकसान से निपटने के समाधान का हिस्सा बन सकता है यदि वह स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के अपने मूल अधिकार के बारे में जागरूक रहे। जैव विविधता संरक्षण के मुददों को तभी सरकार की प्राथमिकता में लाया जा सकता है जब हरित अधिकारों की मांग जनता अपने प्रतिनिधियों से करे। जैव

विविधता संरक्षण और सतत विकास के मुददे कुछ हरित युरोपीय देशों की तरह राजनैतिक चुनावी दलों के घोषणापत्रों का हिस्सा बनना चाहिए। वन्य जीवनए पेड़–पौधे, पर्वत, श्रंखलाएं, भव्य जलप्रपात, गहरे समंदर सब मानव सभ्यता की ओर निहार रहे हैं कि आइए हम प्रकृति के सभी घटक आपसी सामंजस्य मजबूत करें और जैव विविधता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों को हल करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहें ताकि प्राकृतिक असंतुलन के कारण दुबारा इस तरह की महामारी मानव सभ्यता को नष्ट ना कर दे।

किसान आंदोलन का इतिहास

– सूरजभान दहिया

भारत में खेती हर समाज एक अत्याधिक दीर्घकालीन सामाजिक परिघटना का प्रतिफल है। यहां कृषि राष्ट्रीय जीवन और अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार रही है और दीर्घकाल तक रहेगी। निःसंदेह कृषि भारतीय सभ्यता की आत्मा है और इसकी उपेक्षा हमारी धनाढ्य संस्कृति का प्रबल प्रहार है। हमारे कई हजार के इतिहास में ऐसे कई रोमांचक प्रसंग हैं। जब फसल न होने पर राजा ने तपस्या की अथवा स्वयं ही हल उठाया। अन्नदाता किसान को श्रृध्देय माना गया और स्वयं विष्णु–त्रिशक्तियों में से एक ने स्वीकारा था कि भू–लोक में मेरा सबसे अधिक उपासक किसान है जो सूर्य उदय होने से पूर्व ही गऊ के दो जायो के साथ खेत में प्रस्थान होने से पहले यह कर मेरी उपासना करता है– ''धरती मां तू बड़ी तेरे तै बडे भगवान''।

ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जब कृषि एवं किसान की उपेक्षा अथवा उससे भेदभाव करने पर हमारा देश भयावह संकट में पड़ा। अकाल पड़े, भूख से हाहाकार मचा, मौत ने खुला तांडव किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान को ताक पर रख, अपने ऊपर कमर तोड़ कर्ज का बोझ लादकर हमने दूसरे देशों के सामने अनाज के लिये कटोरा भी फैलाना पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी आकांशाए पूरी करने के लिये कृषि तथा किसान दोनों को बुरी तरह उजाड़ दिया था। भारत आजादी के समय खाद्य संकट की चपेट में था। पश्चिमी देश भारत में भुखमरी की भविष्यवाणी करने लगे थे। वह भविष्यवाणी यदि सच हो जाती तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को टूटने में देर नहीं लगती। यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमारे लोकतंत्र का भविष्य टिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में चेतावनी दी थी कि ''हर क्षेत्र में प्रतीक्षा संभव है, लेकिन कृषि में नहीं''। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में प्रतीक्षा खत्म नहीं की गई। सामान्य किसान और खेतीहर मजदूर की झोपड़ी में न लक्ष्मी (समृद्धि) पहुंची है और न सरस्वती (शिक्षा)। हां, बेबसी, शोषण, गरीबी एवं तिरस्कार उसके दरवाजे पर निरंतर दस्तक दे रही हैं।

खेती, किसान और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर सोचने की आदत इस देश में बहुत कम है। यदि किसी कारणवश सोचना पड़ता है तो 'पांच अंधे और एक हाथी' की रोचक कथा याद आ जाती है। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक बार सन् 1965 में पूरे देश ने 'अनाज में आत्मनिर्भरता और अन्नदाता किसान' का महत्व पूरी गहराई से अपने दिल और दिमाग में रेखांकित किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के उद्घोष 'जय जवान जय किसान' ने पूरे देश को ही किसान बना दिया था। अनाज निर्यातक अमरीका की धौंस धरी की धरी रह गई थी। आत्मनिर्भरता के स्वप्न को भारत के किसान ने अपनी मेहनत व देशभक्ति के यथार्थ को कठोर धरती पर उतार दिखाया। उसके बाद देश हरित क्रांति से अन्न के मामले में निश्चिंत हुआ और उसके इस संबंध में लगभग सभी उदासीन। ऐसी स्थिति में यह पुनः मन में बार–बार उठता है कि हरित क्रांति (अनाज में आत्मनिर्भरता), श्वेत क्रांति (दूध में आत्मनिर्भरता) और नीली क्रांति (मछली पालन में आत्मनिर्भरता) का 'अमृत–कुंभ' कौन ले भागा है? कहां और क्यों अटक गई– ग्राम विकास की हरहराती गंगा? क्यों अन्नदाता को दिनोंदिन आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है? क्या यही राष्ट्रपिता बापू के 'हिंद स्वराज' का स्वप्न था?

देश को 'संपूर्ण आत्मनिर्भरता' के स्वप्न की ओर अग्रसित होने का आहवान है इस प्रयोजन हेतु अच्छे साधक (किसान) की आवश्यकता है जो वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं हैं। आज भारत अपनी नीतियों को उदार बना रहा है, लेकिन ये उदारता केवल उद्योगों एवं कारपोरेट घरानों की झोली में जा रही हैं जबकि किसान को खेती की लागत भर भी पैसा नहीं मिलता। किसानों को कारपोरेट जगत के मातहत बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वह देशहित में नहीं है। किसान भारत का प्रतीक है जिसकी अंधेरी रात खत्म होने को नहीं आती।

अब एक विचारणीय प्रसंग। रूसी किसान की दशा पर एक जगह लियो टॉल स्टाय ने अपनी पीड़ा इन शब्दों में उल्लेखित की थी– ''मैं छाती पर सवार हूं और वह घूट रहा है। उसका भला हो। मैं उसकी भलाई और तंदरूस्ती के लिये सबकुछ चाहता हूं। लेकिन वह एक चीज मैं नहीं करूंगा जो किसान को आराम से सांस लेने दे और जीने दे– वह है उसकी छाती (शोषण) से हट जाऊं।'' इसी तरह भारतीय किसान को संबोधित करते हुये इकबाल कहते हैं–

''न समझेगा तो मिट जायेगा ऐ दुनिया के अन्नदाता तेरी तो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।''

गत वर्ष भारत की संसद द्वारा तीन कृषि कानून पारित किये इसी संदर्भ में अवलोकन करने चाहिये। ऐसी विकट परिस्थिति में किसान मसीहा छोटूराम 'बेचारा किसान' में किसान को सचेत होने के लिये कहते हैं–

''ऐ किसान। चौकस होकर रह, चौकन्ना बन। यह दुनिया ठगों की बस्ती है और तू बड़ी आसानी से ठगों के जाल में फंस जाता हे। कोई तुझे शाह बनकर लूटता है, कोई तुझे ब्याज में लूटता है। कभी भाव से तुझ से धोखा किया जाता है। साहूकार तुझे जोंक की तरह चिपट जाता है। हाकीम, हुक्काम तुझे भारी कर्जे तले दबा देते हैं, तुझे लाचार बना देते हैं और परिवार को गरीबी के कुंए में धकेल देते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों से तुझे कौन बचायेगा? कोई नहीं, तो कैसे बचेगा तू? भाई। खामोशी और बेजुबानी से नहीं बल्कि अभियान और आवाज उठाने से। बेबसी से नहीं बल्कि आंदोलन से। संघर्ष कर, गफलत के सपने से जाग, करवट बदल, सक्रिय हो। न्याय युद्ध लड़ना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।''

किसान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने एवं अपनी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य पाने हेतु दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर सरकार से गुहार लगा रहे है। काफी समय हो गया है, किसानों की मांगों को लेकर केंद्रीय सरकार संवेदनशील नहीं दिखती– यहां प्रजातंत्र के नाम पर किसानों के चुने हुये शासक कानून बनाकर 'जनन्याय' का ढिंढोरा भले ही पीटें, यह स्पष्ट है, सारा प्रशासन कुछ वर्ग के हितों हेतु कार्यरत है। यहां के प्रजातंत्र में प्रजा शब्द अर्थहीन है– भारत कृषि प्रधान देश है परंतु किसान की सदैव उपेक्षा हुई है। किसान अपने शोषण के विरूद्ध न जाने कबसे संघर्षशील है। किसान कल्याण के चार स्तंभ एवं मसीहा– बाल गंगाधर तिलक (कोंकण किसान आंदोलन), महात्मा गांधी (चम्पारण सत्याग्रह), सरदार पटेल (बारदोली आंदोलन) एवं छोटूराम (किसान शोषण मुक्ति) सदैव किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिये प्रेरित करते रहेंगे। वैसे किसान संघर्ष की एकलंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसे इतिहास के पन्नों से गायब कर रखा है। वर्तमान किसान आंदोलन निःसंदेह इस सदी का विश्व का सबसे प्रभावी आंदोलन होगा जो अन्य देशों के किसानों को भी प्रेरित करेगा– '21वी सदी किसान शोषण की नहीं अपितु किसान जागरण एवं नेतृत्व की सदी है।''

सन् 1803 में उत्तरी भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अंग्रेजों ने आते ही यहां के किसानों पर भारी भू–कर लाद दिये। राजस्व कर की वसूली न होने की सूरत में भूमि गिरवी अथवा बेचने के लिये अति कठोर कानून भी बना दिये। इस प्रकार के कानूनों से किसानों में एक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया और इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरूद्ध विद्रोह की लहर चल पड़ी। सन् 1828, 1843 तथा 1855 में किसान आंदोलन हुये जिसके परिणामस्वरूप 1857 में जनक्रांति का श्रीगणेश हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार डा. हबीब ने इसे किसान द्वारा संचालित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना तथा स्वीकार किया– ''जब हल उठे तो संग्राम का आगाज हुआ।'' यह किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम की शक्ल ले गया था किसी कारण सफल न हो सका, परंतु यहां आजादी के आंदोलन को नया दिशानिर्देश दे गया था जो 90 साल चला और भारत को 1947 में आजादी मिली। 1857 के संग्राम के कारण न जाने कितने किसान गांवों को अंग्रेजों जलाया, कितने गांवों की नीलामी की गई तथा हजारों–लाखों किसानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी– यह एक लंबा सिलसिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी मार्क थोर्नहिल ने सन् 1858 में ब्रिटिश हुक्मरानों को लंदन में भेजी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था– ''यह चाहे कितना भी विरोधाभासी लगे, पर यह एक तथ्य है कि मेहनतकश खेतिहर वर्ग इस शासन के जारी रहने के लिये सबसे ज्यादा खिलाफ है और भारत में ब्रिटिश राज ज्यादा देर रहने वाला नहीं है।'' भारत के आधुनिक इतिहास में किसान आंदोलन का पहला चरण 1803–1860 काल को माना जाता है।

दूसरा चरण किसान आंदोलन काल 1861–1920 तक समझा जाता है। किसानों की परिश्रमता एवं वीरता के बारे में अंग्रेज अधिकारियों को आभास हो चुका था तथा 1885 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष सर रोबर्ट ने तो साफ–साफ इंग्लैंड में अपने मिल्ट्री डिस्पैच में लिखकर भेज दिया था कि ''पंजाब–हरियाणा तथा दिल्ली के लगते क्षेत्र के बहादुर किसानों की हमदर्दी के बिना भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बने रहना असंभव है।'' फिर भी अंग्रेजी हुकूमत ने पंजाब में तीन कानून– दोआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कोलोनाईजेशन एक्ट तथा पंजाब लैंड एलीनेशन एक्ट 20वी सदी के आरंभ में लाकर किसान आंदोलन के दूसरे चरण को अति ज्वलंत बना दिया। 1907 में बांके दयाल का उत्तेजित गाना ''पंगड़ी संभाल जट्टा...'' लायलपुर किसान प्रदर्शन में गाया गया और यह आंदोलन 9 महीने चला। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक ''ठनतपमक ।सपअम'' में उल्लेख है कि लाला लाजपतराय ने अंग्रेजों की मंशा कि अंग्रेजी सरकार इन कानूनों में संशोधन के लिये राजी थी नहीं, स्वीकारा गया और किसान सभी इन कानूनों को पूर्ण रूप से वापिस लेने के लिए संघर्षरत रहे और किसानों के आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार ने ये कानून वापस लिये।

किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1920 से 1970 तक चला। इस काल में चौ. छोटूराम किसान मसीहा के रूप में अवतरित हुये जिन्होंने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई तथा इस पार्टी की पंजाब में सरकार लंबे अरसे रही। इस दौरान चौ. छोटूराम ने पंजाब में किसान हितैषी कानून बनाकर पंजाब में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को जमीदारा पार्टी के नाम से लोकप्रिय बना दिया। 1941 में सोनीपत में किसान रैली को चौ. छोटूराम ने कहा था– ''आज पंजाब में जमीदारा सरकार है और इसे आपके भाई ही चला रहे हैं। आज पंजाब में किसान राज है यदि किसान इकट्ठे रहे तो कल हम स्वतंत्र भारत में भी किसान राज गठित करेंगे।'' यह किसानों का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि चौ. छोटूराम 1945 में ही 63 वर्ष की आयु में चल बसे। आजादी के बाद किसानों को चौ. चरण सिंह ने कुशल नेतृत्व दिया और उनहोंने 1960 के दशक में अनेक राज्यों में किसान हितैषी संयुक्त दलों की सरकारें गठित करवाई, परंतु यह प्रयास स्थायी न हो सका। चौ. चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने, परंतु थोड़े समय तक तथा वे भारत में किसान राज न ला सके, जिसकी कल्पना चौ. छोटूराम ने आजादी से पूर्व की थी। 23 सितंबर 1978 को दिल्ली में किसान रैली जिसमें 25–30 लाख किसान थे। विश्व की सबसे बड़ी रैली थी, जिसे चौ. चरण सिंह ने संबांधित किया था।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा था तो किसान यूनियनों ने अपने आंदोलनों में तीव्रता लाई तथा वे सरकारों को किसान शोषण के प्रति संवेदनशील होने के लिए दबाव डालती रही। इस दौरान चौ. महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अति सक्रिय हो गये तथा 1988 में दिल्ली में उनहोंने गन्ने के अच्छे दाम देने के लिए लाखों किसानों के साथ किसान रैली निकाली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टिकैत जी की मांग को सहमति देनी पड़ी। उन्होंने अपनी सादगी से यह बात रखी कि लड़ाई तो 'लुटेरों' और 'कमेरों' के बीच है और यह लंबी चलेगी।

लड़ाई तो 'लुटेरों और कमेरों' के बीच है –महेंद्र सिंह टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आजकल एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं, किसानों के 'हक' की लड़ाई तो वे लंबे अरसे से लड़ ही रहे हैं, अब उन्हें अपने 'भाइयों' से भी जूझना पड़ रहा है। देवी लाल की 'गांव बनाम शहर' की लड़ाई में वे उनका साथ देने वोट क्लब की किसान रैली में चले गये। यहीं से उनके खिलाफ बगावत की चिनगारियां उठने लगीं। प्रस्तुत है, दिल्ली से इलाज कराकर सिसौली लौटे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से हुई बातचीत के प्रमुख अंश–

अब किसानों में जागृति आयी है तो वे अपना हक मांग रहे हैं। वैसे 'गांव बनाम शहर' की राजनीति तो सभी नेता कर रहे हैं– चाहे वी. पी. सिंह हों या देवीलाल या फिर राजीव गांधी।

किसान दशक भी मनाया जायेगा, लेकिन किसान अब समझदार हो चुका है। सैकड़ों साल डकैती डालने के बाद यदि कोई एक दिन ब्रह्मभोज कर दे या गरीबों को दान–दक्षिणा दे दे तो क्या वह परम संत हो जायेगा? आजादी के बाद किसानों को तरह–तरह से बेवकूफ बनाया गया है। अब जमीन में गोबर डालकर फसल नहीं ली जा सकती, यूरिया डालना पड़ता है। यही यूरिया किसान को निर्माण लागत से तीन गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। किसान से बीज खरीद कर उसे ही मुनाफा ले कर बेचा जाता है।

तो क्या सरकार भी इन लुटेरों के साथ शामिल है?

ये मुझ जैसा सीधा–सादा किसान क्या जाने? (मुस्कराहट). .. मैं पहले ही कह चुका हूं कि लड़ाई 'खद्दर' पहनने और 'टेरीलीन' पहनने वाले के बीच नहीं है। झगड़ा तो 'टोपीवाले' करवाते हैं। अपनी कुर्सी के लिए वे गरीब जनता को आपस में ही लड़वाते रहते हैं ताकि उनकी स्वार्थसिद्धि हो सके। उनका तो फार्मूला ही एक है कि 'बांटों और लूटो'। आंख खुली हो तो देख लो। तालीम लेने गये लड़के सड़कों पर आ गये हैं। लाठी खा रहे हैं। पर क्या करें मजबूरी है?

'गांव बनाम शहर' यानी 'कमेरों व लुटेरों' की लड़ाई में आपकी क्या रणनीति होगी?

यह सब गोपनीय है।

टिकैत जी ने अपनी विचार धारा 16 सितंबर 1990 को धर्मयुग में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में देश के समक्ष रखी थी।

21वीं सदी वैभव का युग है। 73 वर्ष की आजादी के बाद भी भारत का किसान बदहवास, साहस से शून्य, खोया–खोया सा भटकता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार, मिलावट, कर चोरी, पक्षपात, देशद्रोह, तस्करी जैसे व्यवसाय के माध्यम से खड़ी की गयी गगनचुंबी इमारते राष्ट्र का गौरव की प्रतीक नहीं हैं और इनके नीचे घूमता, ईमानदार, सच्चा, भोला, नैतिक व परिश्रमी किसान घूमता अपने आपको बौना अनुभव करता है। 1929 में भारतीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक गंभीर व संवेदनशील तथ्य उजागर किया था– ''भारतीय किसान कर्जे में जन्म लेता है, कर्जा लादे अपना जीवन गुजारता है और कर्जे में ही अपने सांस पूरे कर लेता है।'' और यह कटु सत्य आजकल चल रहा है। आर्थिक संकट के कारण पिछले कुछ सालों में चार लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। किसी भी गांव में जाइये आपको War Widows (वार–विडोज) तथा Farm Widows (फार्म विडोज) की त्रास्दी का अनुभव हो

जायेगा। यह जय जवान जय किसान की वास्तविकता का परिचायक है।

अभिजात के तीन अंग– व्यापारी, अफसर और राजनेता तीनों एक स्थायी संतुलन स्थापित करने के प्रयास के बजाय स्वयं आपस में लड़ रहे हैं, प्रत्येक अंग शेष दो अंगों से अधिक ताकतवर बनना चाहता है। देश के आर्थिक स्रोतों का अभिजात वर्ग अधिकाधिक हजम करता रहा, शेष बहुत कम बचा, उसमें भी किसान की अत्याधिक उपेक्षा हुई। आज एक किसान परिवार की मासिक आय 9 हजार रूपये से भी कम है यानी एक दिहाड़ी मजदूर से भी कही कम। एक दुखद आश्चर्य है कि किसान को अपनो उत्पाद अपने लागत मूल्य से कम बेचने पर विवश किया जाता है, अन्य सभी उत्पादक अपने सामान को लाभकारी मूल्य पर बेचते हैं। किसान का कोई संरक्षक नहीं है, अतएव किसान विवश होकर दिल्ली की सड़कों पर कड़ाके की सर्दी की रात काट रहा है, हर दिन दो–तीन किसानों की मृत्यु भी हो रही है। परंतु किसान कल्याण मंत्रालय इस ज्वलंत समस्या का समाधान करने में अरूचिकर एवं असंवेदनशील नजर आ रहा है।

जैसलमेर–राजस्थान से 71 वर्षीय किसान पहली बार दिल्ली आया। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने। उसने एक पत्रकार से बातचीत करते समय बताया– ''मैं 52 डिग्री के तापमान के उबलते रेत में अपने खेत में खड़ा रहता हूं तो मेरा इकलोता बेटा सियाचन पर –20 डिग्री के तापमान पर जमा एक चट्टान बनकर देश का प्रहरी बना खड़ा रहता है– भला मेरा परिवार इससे ज्यादा कौन सी देशभक्ति का परिचय दे? यह कैसा लोकतंत्र जिसके रहनुंमा–सांसदों को न तो किसान इतिहास का ज्ञान है और न ही सैनिक इतिहास का फिर भी वे झूठेनारों व आश्वासनों से किसानों को गुमराह करते रहते हैं– अनुभूति सुखद नही। श्रीराम ग्रामवासी भी थे और वनवासी भी। उनकी पत्नी सीता भूमि से पैदा हुई, भूमिजा थी, वन्यकन्या थी। यह दंपत्ति– किसान दम्पत्ति का पर्यायवाची है– राम–सीता श्रृध देय हैं– इसी भांति किसान दंपत्ति भी। किसान दंपत्ति की उपेक्षा भारतीय मूल संस्कृति का घोर अपमान है। किसान शोषण सामग्री नहीं– भारत का प्रथम नागरिक है। वर्तमान किसान आंदोलन ग्रामीण भाईचारे की महाशक्ति है जो असली भारत– गांव का प्रतिनिधित्व करता है तथा गणराज्य व्यवस्था का प्रतीक। इसलिये आंदोलनरत है ताकि उसे भी आर्थिक संपन्नता मिले। अब इस देश में कोई किसान मुंशी प्रेमचंद का न होरी रहेगा न शंकर, बस यह समझ लेना चाहिये कि भारत किसानराज अर्थात रामराज की दहलीज पर खड़ा है।

जय हिंद और जन, गण, मन अधिनायक....

नौजवान व वरिष्ठ नागरिको को समर्पित

एक बड़ा पावरफूल रिमांडर है
कि जिसे हम बुढ़ापा कहते है
वो शायद लाईफ के सबसे गोल्डन ईयरस है
जीने की असली उम्र तो 60 है
बुढ़ापे में ही असली ठाठ है।
ना बचपन का होमवर्क
ना जवानी का संघर्ष
ना 40 की परेशानियां
बेफ्रिक दिन और सुहानी रात है
ना स्कूल की जल्दी
ना ऑफिस की किटकिट
ना बस की लाईन
ना ट्रैफिक का झमेला
सुबह रामदेव का योगा
दिनभर खुली धूप
दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है
ना मम्मी डैडी की डांट
ना ऑफिस में बोस की फटकार
पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार
इज्जत से झुकते सर
सबके लिए आशीर्वाद
और दुआओं की भरमार है
ना स्कूल का डिसिपिलिन
ना ऑफिस में बोलने की पांबदी
ना घर पर बुर्जगों की रोकटोक
खुली हवा में हंसी के ठहाके बेफ्रिक बातें
किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद है
जीने की असली उम्र तो 60 है
बुढ़ापे में ही असली ठाठ है
खुश रहे हेल्दी रहे
हमारे समाज में सीनियर सिटिजनस की बड़ी अहम कान्ट्रीब्यूश्यन है।

Exit of Subhash Bose from Congress

R. N. Malik

शेष पिछला अंक के पेज–17 का आगे

Cunningly, he was pushing Subhash to tender resignation. Instead of writing letters, Subhash should have confronted Gandhi Ji personally along with Nehru and put straight argument before him saying," Mahatma Ji, according to Pant resolution, the Working Committee has to be according to your wishes. So either give names or ask Pant to withdraw the resolution. Now you have to decide this way or that way and you cannot shik your reponsibility any more." Gandhi Ji had to take the decision.

Subhash was being pressed by his leftist supporters, particularly by M.N.Roy, to give an ultimatum to Gandhi Ji to suggest the names failing which he should go ahead with his own Working Commitee. But Subhas was hesitant to take this drastic step. Gandhi Ji was dodging Subhash because he knew that Subhash and Congress would never work cohesively inspite of the patch up. He himself had reservation about Subhash having complete faith in nonviolence. He had observed a streak of militancy in Subhash when he appeared in a military uniform of a general at Calcutta session in 1928. According to Kriplani, Gandhi Ji knew his relations with militant or revolutionary groups. His meeting with Germany embassy people was still fresh in his mind. But his main problem was that he always made hasty decisions or observations without examining pragmatism and weighing prons and cons of the situation. For example, he suggested in the Lahore session to form a provisional government that was not possible. Gandhi Ji also thought that Subhas would initially start the movement on nonviolent lines but will change gears at a later stage. That is why he wanted that Subhas should leave the Congress. But Gandhi Ji should have courage to point out the deficiencies in the working of Subhash rather than push him out by sleight or stealth. In fact Gandhi Ji himself was violating Pant resolution by not helping Subhash to constitute the Working Committee.

Subhash invited Jawaharlal at his place in Jamadoba on 20th April. The two met with great warmth. Their views concurred and the two decided to make the last effort to settle the issue with the patriarch who had arrived at Sodepur Ashram near Calcutta after suffering a political defeat at Rajkot. Subhash and Jawahar held talks with Gandhi Ji for two days but Gandhi Ji refused to suggest names for the CWC holding the old argument that he could not impose his will on the new President. He also suggested Subhash to hold talks with the members of the preceding CWC to arrive at a final composition. This again was a cunning way to put off Subhash and keep the pot boiling knowing fully well that ego problems of both sides would not yield any result. Subhash was not Mahatma Gandhi who had no hesitation to meet his opponents. Fault of Subhash and Nehru was that they did not assertively tell Gandhi Ji," Mahatma Ji, as per Pant resolution, you have to give or suggest names to constitute the new CWC. Either you give the names or ask Pant Ji to withdraw the resolution in the coming AICC session. You have to decide the smouldering issue this way or that way. By not fulfilling your responsibility, you are simply violating the dictates of the Pant resolution and also shirking your own responsibility in the stand off. Otherwise, it will be deemed that you are deliberately procrastinating the issue to compel me to resign." Subhash understood what Gandhi was up to and prophesy of M.N.Roy was coming true.

AICC held its session at Calcutta on 29th April. Sarojini Naidu was in the Chair. Subhash tendered his resignation. The resignation letter said," Initially, Mahatma Ji advised me to constitute the Working Committee leaving out the members who had resigned on 22nd February1939. (Only Sarat Bose and Nehru had not resigned.) But such a CWC would not be according to the dictates of Pant resolution. Then Mahatma Ji advised me to consult the preceding CWC members to arrive at an agreement... Unfortunately ...we could not arrive at a settlement. (No such meeting took place.)..Now I feel that my presidentship may become an obstacle in smooth running of party affairs...It may be easier for AICC to settle the issue by electing a new President. After mature deliberation and in a helpful spirit, I am placing my resignation in your hands.". He did not make express request for its acceptance.

Now Nehru, who had been privately pressing Gandhi Ji for effecting an acceptable solution, moved a resolution requesting Subhash to withdraw his resignation and keep the old CWC and add two members of his choice in place of two ailing members. Only Jaiparkash Narain and Rafi Ahmad Kidwai rose to support the motion. Others kept mum and Subhash could understand this silence. The meeting was adjourned for the next day.

The following day, Subhash made it clear that he could work only with a truly representative CWC and again pleaded that his resignation was in the hands of the AICC meaning thereby that he did not agree with the suggestion of Nehru and he could withdraw his resignation provided AICC constituted a more representative CWC by including some members of leftist leanings. Finding no response to his suggestion, Nehru withdrew his resolution. Accordingly, resignation of Subhash was accepted and Rajendra Prasad was elected as the new President. Nehru refused to be a member of the new CWC. Dr. B.C.Roy and P.C.Ghosh were added new members in place of Nehru and Sarat Bose. It was another slap on the face of Subhash as Sarat Bose was not retained in the new CWC. People of Bengal were bubbling with rage as Subhash was being battered and humiliated before their eyes and on his home turf. All the members had to be extricated out of the session with the help of security personnel. Subhash now realised that there was no place for him in the Congress but he would not leave it at. any cost. But delegates again attacked unarmed Subhash like Abhimanyu in Mahabharata. Firstly, they did at Tripuri. Gandhians again behaved in non- Gandhian way. Truly, it was the brazen or ignominious defeat of Gandhians and not of Subhash. Great men became small after a long time.

Gurudev Tagore congratulated Subhash for his bold action. He wrote," The dignity and forbearance you have shown has won my admiration and confidence in your leadership." Gurudev also gave him the title of Deshnayak. Subhash wrote to Emilie," India is a strange country. Here people love and respect a person when he gives up power rather than he assumes power. I got warmer reception in Lahore after the resignation than last year when I went there after becoming the President."

The concept of leftist, socialist and rightist has been the bane of this country till today. It has been the bane of Congress till 1947. Subhash too had been deeply bugged by leftism and socialism both. He could not differentiate between the two concepts. He used the terms 'socialist and socialism' quite often in his long presidential address at Haripura. All this debacle in the Congress was also the outcome of this left vs right though Gandhians never talked of their being rightists. In fact they were more Gandhians than rightists.

However, British government was very happy at the exclusion of Subhash from the Congress. Otherwise he could take the party towards a radical path. Subhash was irrepressible as Gandhi Ji would later call. Within a week of his resignation, Bose announced the formation of 'Forward Block ' a group within the Congress like Swaraj Party within Congress in 1923 or Socialist group of Jaiparkash Narain and Dr. Ram Manohar Lohia within the party. The object was to rally all radical and anti-imperialist progressive elements in the country on the basis of a minimum program. He had hoped that all the ginger groups that supported him during the presidential election would join the block. But these groups were not prepared to lose their identities. Six weeks later, at the All India Forward Block Conference at Bombay, it was decided to form a Left Consolidation Committee which again would be a loose group representing all shades of opinions. The aim was to swing the Congress program towards radical program of Subhash Bose that stood for four objectives I.e. promoting left policies, ultimatum to the Raj to grant Purna Swaraj, exploitation of international situation as it unfolded from time to time and take steps to make Socialist India after independence. The Committee had equal representation from CSP, Royists, CPI and Forward Block. Some preliminary meetings were held but these mostly ended in bitter fights between CPI and CSP representatives. Accordingly, very soon, the whole concept proved to be a pipe dream. Subhash quickly grasped the reality and he too abandoned the idea and started touring whole of India and address meetings as Head of the Forward Block. Important members of the Block were Sardool Singh Caveeshar in Punjab, Akbar Shah in NWFP, H.V. Namath in Bombay, Swamy Sehjanand in Behar, N.G.Ranga in Andhra, Indulal Yagnik in Gujrat and Hosmani in Karnataka. The redeeming feature of the new outfit was that people came in large numbers to hear the radical views of Subhas. His program of addressing meetings continued up to June 1940. His pet theme was the criticism of Congress top brass for its vacillating and compromising nature. He portrayed himself as a courageous rebel, a challenger of status quo in the Congress, converting constitutional mentality of Gandhians with fighting mentality of Forward Block. He identified himself with the youths and exhorted them to join in his manly fight agaist reactionary forces of imperialism. In this way, his fight against Congress was more than the fight against the Raj. Some wise people like S.Satyamurti, Biswanath Das (Premier of Orissa) and Harekrishan Mehtab pointed out to Subhas that he was harming Congress more than the Raj.

Subhash Bose was still the President of Bengal Congress Committee. Fearing the misuse of that position, AICC passed two resolutions in June 1939.

1. Prohibiting Congress members from offering Satyagraha without the permission of CWC.

2. Congress provincial Ministries to be free from the need to follow the directives of Provincial Congress Committees.

Bose asked his group to hold demonstrations on 9th July against the attempts of High Command to stifle the intra-party democracy. Accordingly, meetings were held at number of places. Subhash addressed a big meeting at Bombay. CWC urgently charged Subhash for violating party discipline and banned him from holding any elective office in the party for three years. So Bose was automatically dethroned from presidentship by the ban. Accordingly Congress party in Bengal was also divided into two factions. Majority was in the Bose group and minority was brought under an Adhoc Committee headed by Kalam Azad. The legislative wing was also divided. The Bose group was led by Sarat Bose and the other group was led by Kiran Shanker Roy. Disciplinary action was taken against Sarat Bose also. All this was happening due to the leadership failure of Gandhi Ji. He could have brought the unity between the two groups had he so desired. He was so passionate about Hindu-Muslim unity (and rightly so) but showed little care to bring unity in his own party at this crucial juncture.

In December 1939, Gurudev Tagore again asked Gandhi Ji to lift the ban on Subhash for the sake of unity in the party. Now rapprochement was impossible as Subhash had gone too far and had started using very hard words against Gandhi Ji and other seniors. The words like Gandhism, Gandhians and rightists were themselves were highly disrespectful to Gandhi Ji and other leaders. For example, while addressing a Student Conference, he said," Patriots had to be wary of a Gandhian compromise with imperialism.Why are they thus shrinking a struggle? I presume that once a nationwide campaign is launched, the leadership and control of movement will pass out of their hands. Rightists are out of touch with the emergence of new forces. Moreover they have lost contact with Muslims, Kisan movement, Working class movement. Student movement, Youth movement and other radical movements." That is why Gandhi Ji conveyed to Gurudev through Andrew," If you think it proper , tell Gurudev that I have never ceased to think of his wire and anxiety about Bengal. I feel that Subhash is behaving like a spoilt child of the family. The only way to wake him up is to open his eyes. And then his politics shows sharp differences. I am quite clear that the gap is unbridgeable. I am quite clear that the matter is too complicated for Gurudev to handle. Let him trust that no one is personally against Subhash. For me, he is my son." What Gandhi Ji wrote was not quite true but his not responding to Gurudev directly was an unpalatable act. Gurudev must have taken this act with a pinch of salt.

At another place, Subhash said," I warn all those who listen to me of the potential compromising tendencies of Gandhian run Congress.Since the CSP(Socialists) and some other leftists have sided with the Gandhians.These so called leftists cannot wear that label." Subhash also tried to reach out to Jinnha and Savarkar around March 1940. Jinnha bluntly told him to first take control of Congress and then talk. He found Savarkar too narrow minded.

Matters came to a head in March 1940 when Congress held its annual session at Ramgarh in Bihar under the presidentship of Azad. Subhash addressed an Anti-Compromise Conference at the same place that was largely attended. This time, he did not talk of Gandhism, compromise and rightists. He simply said that Allies were beating a hasty retreat against German forces and England was being pushed to the wall. So he suggested that it was the best time to launch

the nationwide freedom movement and accused Congress for dissipating that opportunity. He addressed another conference at Nagpur in August and said the same thing there as well. Lastly, he made another effort to bring around Gandhi Ji not to lose the propitious opportunity to launch the nationwide movement. So he went to Wardha from Nagpur and met Gandhi Ji. But Gandhi Ji maintained the same stand that the nation was not ready for a nationwide movement and he smelt violence in the air. It was a fact that a movement by Gandhi Ji with Subhash on his left side and Sardar Patel on the right side would have drawn large number of people to jail but restive youth would have definitely indulged in large scale violence.

Subhash knew his own limitations and was afraid to launch the movement unilaterally under his own leadership even though his meetings were largely attended. Even on Ist September 1939 when Germany attacked Poland, he was addressing a mammoth meeting of two lac people at Madras. Still he was believing that a nationwide movement could succeed only under the leadership of Gandhi Ji. So his 16 months campaign against Congress proved counter productive. His limitations were two. Firstly, he would be immediately arrested along with his brother. Secondly he knew that both he and Sarat could not bear the rigours of jail life because of their poor health. That is why he was imploring Gandhi Ji to initiate the movement. Gandhi Ji was afraid that Churchill would crush the movement with a firmer hand than Willingdon. Things were different under Chamberlain. So he was waiting for more opportunate time and that time came in August 1942 when he did not listen to anybody and launched the famous Quit India movement. Now separation of Subhash with Congress was complete.

Congress and the 2nd World War

Congress Ministries were doing wery good work in eight provinces. The Governors of U.P. and Madras wrote articles praising the good work being done by the Provincial Congress governments under Pant and Raja Ji. People too were very happy with the performance and started feeling as if Swaraj had already arrived. Lord Linlithgow, the Viceroy, too was very happy to see the successful working of self government under the supervision of the Raj. His happiness was justified because he had drafted the Act being Chairman of the Select Committee. His only regret was that Federal part of the Act could not take any shape. (Congress did not give a cogent reason for not accepting the federal part. But it lost a great opportunity to rule whole of India and could achieve many milestones.).But this sentiment of happiness continued only for two years. On 1st September 1939, Germany attacked Poland both in the air and on the ground with a massive thrust and everything went topsy turvy. England declared war against Germany. The Viceroy lost no time in declaring war against Germany on behalf of India without consulting the people of India and their leaders. All political parties except Unionist party of Panjab had held demonstrations in whole of India when Simon Commission visited India in February 1928 simply because it did not have a single Indian in its composition. Now no political party took an umbrage at the arbitrary action of the Viceroy for not consulting Indian leaders and her people before declaring war against Germany though India did not have any enmity with Germany. This lapse was much more serious than all-white composition of Simon Commission. Congress felt cheated on this score but did not lodge any written protest against the Viceroy. This issue could have been a rallying factor of a nationwide protest against the Viceroy but not a dog barked. However there was lot of anger in the hearts of the people with nationalist feelings and accordingly most people aspired for German victory.

The Viceroy called Gandhi Ji from Wardha to meet him at Simla where he was residing at that time. Gandhi Ji along with Sardar Patel reached Simla and met the Viceroy on 4th September. In one to one meeting, the Viceroy implored Gandhi Ji to support the war effort as he had done during the 1st World War. Gandhi Ji told the Viceroy that he was looking at the war with an English heart and could not see the destruction of London without being stirred to the very depths of his being. Then he conjured the picture of Westminster Abbey and the Parliament buildings destroyed by German bombs. Momentarily, Gandhi Ji became emotional and tears started dropping from his eyes. Even the Viceroy was astonished at the surge of his emotions. Then Gandhi Ji controlled himself and told the Viceroy that he was for extending non-violent unconditional support for the war effort but he could not speak for the nation and the CWC. The dropping tears won the respect and warmth of the Viceroy in future meetings but the shrewd Viceroy, like any other diehard Tory, never responded positively to his pleadings.

Gandhi Ji held the Press Conference and repeated his version without tears. It is not known whether Sardar Patel and Gandhi Ji discussed with each other what to say to the Viceroy during the train journey. Patel would have never advised Gandhi Ji what he actually told the Viceroy. During the return journey, people in large number came to see Gandhi Ji where ever the train stopped in the way and questioned him for showing so much sympathy to Britain and asked him why he forgot the Jalianwala Bagh tragedy for which he had to launch nationwide movement that ended in complete failure and also why did he not protest against dragging India into the war against Germany arbitrarily by the Viceroy. Gandhi Ji had no answer.

Coming back, Gandhi Ji invited an All Party Meeting at Wardha on 9th September to discuss the future course of action in view of the request of the Viceroy. No party responded to his call. But CWC members arrived. Jaiparkash Narain, Subhash Bose, M.S.Aney and Narendra Deva were the special invitees. Jawaharlal Nehru was in no mood to placate the Raj. He was even against forming the ministries. Earlier he was chagrined when Gandhi Ji had decided to suspend the Civil Disobedience movement in July 1934. So he prepared a draft statement that was discussed for three days by the CWC . Gandhi Ji pleaded for nonviolent unconditional support to England. His pleading was based on following four grounds.

I. No other political party or organisation was interested in independence. These are looking for seeking their own political gains. It does not matter to them at all if the Britishers rule India for another 100 years.(Earlier Viceroy had informed Lord Zetland, Secretary of State for India, that Raj had become a ticking bomb and except for Gandhi, all the principal players including leading princes, were waiting for an excuse to set it off in hopes of building their own order out of the rubble.)

2. In earlier movements, Muslim League and Ambedkar did not join hands with Congress. Otherwise they also did not oppose the movements and kept mum. But this time, they would exploit the situation and might create conditions for violence. The government will also practise the Divide and Rule policy to the hilt.

3. People were tired and were not ready for a long drawn out and sustained Civil Disobedience movement. Attending meetings in large number was different from going to jails for long periods.

4. Government would deal with the movement more harshly than what Willingdon did in 1932.

Neither any member asked nor Gandhi Ji bothered to explain himself what he meant by nonviolent unconditional support as any support in the theatre of war would be deemed as the violent support. In Mahabharata, Lord Krishan did not carry any arm and only drove the chariot of Arjun. That probably was the nonviolent support. However CWC shot down the proposal of Gandhi Ji unanimously and approved the draft statement prepared by Nehru.

The resolution had a long narrative on the evils of both fascism and imperialism and talked about the need for end of colonialism both in Asia and Africa. It stated three things so far India was concerned.

I. The government should declare its war aims and their application to India.

2. If the government declared that the aims included elimination of imperialism and treatment of India as a free nation, then Congress was prepared to extend its co-operation.

3. The friendship between India and England was possible but only on equal terms and a lorded over India cannot fight for the freedom of India.

There was no need to pass a long-winded resolution in circumlocutry terms. Similarly, there was no need to ask for war aims because England was not the aggressor. Declaration of war against Germany at that moment was only to sympathise with Poland and that too as a defender. England launched the war only she sent her warships to defend Norway against the German attack on ... and the attempt ended in a disaster that further led to the resignation of Prime Minister Chamberlain yielding place to Churchill. Churchill took over as the new Prime Minister on 10th May 1940. The resolution should have straight away said in direct terms that," Congress will extend wholehearted support to the war effort provided the government grants full Dominion Status to India during the war followed by complete independence after the war. It is an irony that England is ready to fight for the freedom of Poland and is not ready to grant independence to India whose men, materials and other resources are purported to be used so brazenly and that too for the independence of a third country. So why should Indian soldiers be used when you are enslaving their own country.. 20 lakh soldiers fought for England during the 1st World War and 77000 lost their lives and what did England gave to India in return? Jalianwala Bagh massacre and Martial Law for one year! If England is not prepared to concede basic right of freedom to India, then Congress will launch a massive mass civil Disobedience movement till freedom is attained." This kind of resolution would have frightened the already depressed Prime Minister of England. Also it would have electrified most of India. Subhash too would have been very happy who like Annie Besant had said that difficulty for India was a rare opportunity for India to yield England on her knees. That theoretical resolution of CWC served no purpose to shake up British government in England.

Linlithgow called 52 political personalities to have their views. Subhash met on 10th October and made the aforesaid statement. Princes who ruled ten crore population and half of geographical area were more than enthusiastic to give full support to the government. Jinnha put up only one simple demand in exchange of support : treat Muslim League as the sole representative of Muslims of India in future consultations meant for constitutional development. Unionist Party , Ambedkar and Krishik Praja Party of Fazlul Haq also gave unconditional support to the Viceroy. Now Congress party was left alone to crave for Independence and was sitting on the other side of the fence. Others had no value for liberty and independence. Armed with so much support, the Viceroy called the demand of Congress as pure blackmail. He wrote to Zetland that Divide and Rule policy onward would be enough to blunt the non- co-operative efforts of the Congress. When Sardar Patel met Linlithgow, the later told him that support of Muslim League, princes and others was enough to meet the demands of the war. Sardar Patel realised that what Gandhi Ji was saying was right.

Federal part of the Act had provided limited Dominion Status. The Act provided three departments I.e. defence, external affairs and police directly under the control of the Viceroy. But after the war, the Viceroy had been invested with veto power even to have control over the functioning of the provincial governments. So there could be no meeting point between what Congress wanted and what the British government could give. CWC even did not discuss in three days what steps it would take in case its demands were rejected. The conveyed its response to the CWC resolution on 17th October 1939. It said," Her Majesty's Government (H M G) have not defined with ultimate precision their detailed objectives in the persecution of war. However, after the war ended, Indians could hold constitutional talks with the British government. During the war, the Congress could, if it wished, send representatives to a consultative committee."

CWC members were shocked and disgusted at the denigrating response of HMG. Now their eyes were partly opened and they could sense their values in the eyes of the Raj. Otherwise the reply was on expected lines. Gandhi Ji met the Viceroy twice to have an honourable pact with Congress. But Linlithgow, a deceptively polite person, expressed total disagreement with Gandhi Ji. The main requirement of the Raj was recruitment of soldiers. Young people were making bee lines before the recruitment offices for enlistment because of pressure of unemployment and poverty and desire to see Europe. Now both Congress leaders and Gandhi Ji were thoroughly distraught and disconsolate. In a huff, CWC asked the provincial ministries to resign. This is what the Viceroy, Jinnha and others wanted. This was the most foolish act of the CWC. Gandhi Ji said that loss of office was better than loss of face with the people. Jinnha called this step of Congress as its demise and sunrise of League. He called a public meeting on 22nd December at Bombay and called it a Day of Deliverance from the Hindu Raj. Ambedkar also joined Jinnha on the stage and spoke very bitter words both about Gandhi Ji and Congress. Next day Jinnha held meetings with Ambedkar, Savarkar and Ramaswamy Naiker. Gandhi Ji asked Jinnha to lead all anti-Congress forces in India but fight for the independence of India. Shred Jinnha did not take the bait. More meetings were held by Muslims throughout India. Observing the size of the gathering and the geographical range, Jinnha felt that he had become the accredited leader of Muslims of India. Sir Sikander Hyat Khan and Fazlul Haq also started feeling small before Jinnha. Now Jinnha decided not to waste time in having dialogue with Congress

leaders for reconciliation anymore. His focus now was to father a Muslim nation and go down as the greatest muslim in the pages of the history of that nation.

Congress was responsible for its present plight. The main drawback of the party was that it lacked professionalism. Gandhi Ji was running the party like a family affair. Subhash did not know how to avoid an avoidable jail term. He was also rash and non-conformist. There were clear fault lines between rightists, leftists and socialists. Gandhi Ji always kept his cards close to his chest and rarely called members for mutual discussions. Nobody was worried about the widening gap between Hindus and Muslims except Gandhi Ji. Gandhi Ji devoted most of his time in answering letters, meeting people and always thinking of his construction program. Though the Construction program was very important but it could not take precedence over freedom movement. Congress party did not send permanent unofficial ambassadors in England, America and Russia to sway public and media opinion in its own favour. Moreover, there was no long term planning for the future. Senior leaders always put the ball in the court of Gandhi Ji. His spritual ascendancy always had the intellectual blind spots. Strategic planning was totally missing as Gandhi Ji always squarely believed in his instincts. Saints are always square pegs in the round holes politics. Muslims were feeling alienated because Congress was ruling in 8 provinces and it took little care to induct nationalist Muslims in various slots. Muslim representation was very little in the ministerial slots. Of course, the two dominant Muslim provinces(Bengal and Punjab) were having Muslim Premiers. But neither Gandhi Ji nor the top brass sat together to develop a strategy to belittle Jinnha. Gandhi Ji deliberately did not allow to have a coalition government in Bengal with Krishak Praja Party. It did not seek the help of Sir Chhotu Ram to win over Unionist party to counter the influence of Jinnha in Panjab. Sir Sikander Hyat Khan attended Lahore conference of Muslim League and declared Jinnha his leader. But Sikander died in 1942 and Khijjar Hyat Khan became the new premier. He always kept Jinnha at an arms length. NWFP was governed by Khan brothers who were devout Congressmen. So it was easy to encircle Jinnha by having rapport with other powerful Muslim leaders. But Gandhi Ji spent lot of time and energy in wooing Jinnha who cared a fig for him. Being a brilliant lawyer, he was fighting the case for an independent Pakistan with step by step approach on the pattern of a legal battle in a court. On the other hand, Congress was not focussed on any issue. It could not even win over Dalit leaders. It did not counter the propaganda of Jinnha calling Congress a Hindu organisation and governance in 8 provinces was nothing but Hindu Raj with full facts and figures. Congress was now facing four powerful opponents at a time I.e. Jinnha, Government, Ambedkar and Hindu Mahasabha. Jinnha had none. After the resignation of 8 provincial ministries, Congress had become powerless and was standing at the crossroads. Subhas was holding mammoth rallies and was criticising Congress and Gandhi Ji openly for its lukewarm approach towards freedom movement. He was addressing a rally of two lac people at Marina beach in Madras on 3rd September 1939 when somebody told him that the Viceroy had declared war against Germany on behalf of India. Gandhi Ji was solely responsible for creating serious fault lines in Congress in Bengal. In fact, Congress did not have a thinking and focussed leader like Jinnha. Subhash was the only orator with Congress. He too had been expelled from the party. So the entire freedom movement had been going wayward during the Gandhi era. Initially there was unnecessary fight between no changers and Swarajists. Now it was amongst rightists, leftists and socialists.

Congress held its annual session at Ramgarh under the presidentship of Dr.Kalam Azad in March 1940. Subhash also held his conference near the same place. So two conferences at the same place and at the same time sent wrong signals to the masses. Jinnha held his massive conference in Lahore in the same month. It was attended by 60000 Muslims. Jinnha harped on multi nation theory when he said that Indian was not a nation but a continent composed of multiple nationalities and Hindus and Muslims were two separate identities and yoking them under one nation will destroy the very fabric of governance. So he asked Fazlul Haq to move the resolution for demanding two separate sovereign states where Muslims were in majority in geographical contiguous units both in western and eastern sides of India. He did not use the word 'nation'. At present it meant that India should be politically structured like United Kingdom composed of three autonomous states like Scotland, Ireland and England. But Jinnha was not to rest content at this position. His next step on the ladder was formation of an independent country. Somebody from England had coined the name proposed Country as Pakistan. So people started calling Lahore resolution as Pakistan resolution.

Churchill became Prime Minister of England on 10th July. By that time, Hitler had captured Denmark, Norway, Holland, Luxumberg and Belgium. France was about to fall. Now Churchill was feeling alone to fight against Germany. But he had nerves of steel. Zetland resigned as Secretary of State and was replaced by Leo Amery.

With the arrival of Churchill, there was absolutely no chance of getting any concession from the Raj. He had even opposed the holding of Round Table Conferences in 1930 and 1931. He did his best to stall the passage of 1935 Act.(read details in Annexure I) Now he made it clear to Leo Amery and others that retaining control over India was as important as defeating Hitler. He further told that Great Britain would no longer remain Great Britain if India went out of her hands. And India, 'The Crown Jewel' of empire had become the embossed seal of British greatness. Leo Amery had great differences with Churchill over Indian affair. He had felt that Churchill had gone insane so far as dealing India was concerned. Secondly, he had believed that any suggestion of self government to African and Asian colonies created a fearful complex in the mind of Churchill. So Churchill was both imperialist and racist. In July, Amery suggested Linlithgow to declare some concessions to meet the demands of Congress halfway on 1st September 1940. Churchill was furious with both Amery and Linlithgow when he got wind of this movement. So Gandhi Ji and Congress was required to change the strategy completely if it had to see any chance to beat Churchill at his own game. There was one thing common in Churchill and Gandhi Ji. Churchill had will power to defeat Hitler. Gandhi Ji had full faith in Satyagraha to defeat Churchill.

France was lost by 30th June. Only English Channel separated German forces and England. Hitler was still thinking to attack England by shipping its army to the other end of the Channel. Then the Chief of German Air force told Hitler that he would be able to doom England in two months by air raid bombing which he could not. So the plan to attack England by sea was aborted. That decision saved England.

There were other options to defeat England which Hitler did not try. There was also a belief that Hitler did not want to defeat England because he felt that Germans and Britishers belonged to the same teutonic race.

Therefore finding England being pushed to the wall, Raja Ji suggested to the CWC that another feeler should be sent to England for extending co-operation in exchange of full Dominion Status during the war and complete independence after the war. Subhash and Jaiparkash Narain opposed this move from jail and advocated for mass Civil Disobedience movement. (Subhash was arrested on 7th July 1940 in Calcutta before launching a movement to remove the bust of Howell.) Gandhi Ji opposed the move on the ground of his earlier principle of non- violence. He still believed in the dictum" Nothing is stronger than an idea when its time comes." He still felt that time for a mass movement had not arrived. CWC did not agree with Gandhi Ji and approved the idea of Raja Ji. The issue was put before AICC in its meeting on 27th July in Poona. AICC too endorsed the proposal. Khan Abdul Gaffar Khan resigned from the Congress as he endorsed the reasoning of Gandhi Ji.

Poona offer was wired to England. The reply came quickly on 8th August through a Viceregal statement. It said," Provided the Raj, the Congress, the Muslim League and the Princes reached an agreement, some politicians would be included in the expanded Viceroy's Executive Council in which Viceroy will retain his veto power. At the end of the war, a body will be set up, with least possible delay, to devise the framework of a new Constitution. A shocked Raja Ji had to eat his humble pie. Sardar Patel took the vow never to ignore the advice of Gandhi Ji in future.

All the Congress leaders have been behaving like novices. British Government (both Tory and Labour) had been steadily maintaining that it was the moral duty of England to take paternalistic care of India as well and they would settle minority question first and everything later. Gandhi Ji wanted independence first and all other questions to be settled among themselves later. British M.P.s did not see Gandhi Ji more than an astute politician. Secondly , the last milestone in British thinking was granting full Dominion Status to India in stages. How many steps were needed ro be climbed was not yet ascertained and granting independence was a very far cry. It only had to be snatched. Could mass Civil Disobedience attain it under the given circumstances when Princes, Muslim League and Dalit leaders were on the other side and goverment clamping the 1932 like crack down. Congress did not plan its strategy accordingly in view of aforesaid reality and was still living under some illusions.

Now Congress leaders called upon Gandhi Ji to guide them to save their skins. Gandhi Ji suggested to launch limited Civil Disobedience so that Congress remained floating in the imagination of people and the government was not greatly embarrassed to provoke to impose crack down. It was called Individual Civil Disobedience or ICD. It was launched in October 1940 under the leadership of Acharya Vinoba Bhave. Gandhi Ji was advised not to take part so that he remained in touch with situation outside jail and take appropriate steps. About 15000 Satyagrahis took part in this movement and were put behind bars and sentenced to varying durations.

After the arrest of Vinoba Ji, Jawaharlal was arrested on 31st October. He was charged with sedition and sentenced to four years of imprisonment. A stream of people continued till summer months in the next year. All the Satyagrahis were sentenced with imprisonment varying between 9 and 15 months. Sardar Patel was released in August 1941 because of some serious health problems. Raja Ji was released in October. During the jail, Raja Ji received a message from Sikander Hyat Khan for a joint Congress-League move. But the Viceroy pressurised Hyat Khan to abandon the effort. All the ICD prisoners were released on 4th December 1941.Nehru too was released after undergoing spending a period of 13 months. Most Satyagrahis had completed their period of imprisonment.So Nehru could not kept alone in jail.So he too was released along with others.

Luck smiled on Churchill twice after May 1941. Firstly, Hitler attacked Russia on 21st June and got engaged in a long drawn out war with Russia that continued for four years and ultimately led to the nemesis of Hitler, German army and the World War itself. When Churchill heard of this news, he sighed with a great relief and remarked," Now Hitler cannot attack England." Luck smiled again when Japan attacked Pearl Harbour on 7th December 1941. Churchill again sighed with great relief and remarked, Now we will win because America has entered the war." America had stopped all the exports to Japan including oil. Japan decided to attack other colonial states in Asia to get a foot hold on oil and other mineral resources. These countries namely, Hongkong, Philipines, Siam, Indochina, Malaya , Singapore, Burma were under the subjugation of France, Holland and England. Since France and Holland were under German occupation, they had no right to keep these countries under their subjugation. So Japan attacked the big naval base of America at Pearl Harbour to cripple her for future attacks on Japan for at least six months and damaged many war ships of America. But these ships were damaged but not destroyed and were quickly repaired. So Am er ica also declared war against Japan, Germany and Italy.

Cripps Mission and Quit India Movement.

Churchill's delight at bombing of Pearl Harbour was shortlived. Three days later on 10th December, Japanese dive bombers and torpedo planes sank two great battleships 'Repulse' and 'Prince of Wales' of Royal Navy killing 1000 soldiers. 'Prince of Wales' was of special significance to Churchill as he had a historical meeting with President D. Roosevelt on this ship for signing the Charter for Freedom. When Sir Dudle Pound, First Sea Lord, conveyed this sad news to Churchill, he was shocked beyond measure. He wrote later," Thank God, I was alone. In all the war, I never received a more direct shock.The sinking of these two ships was more earthshaking for Britain than attack on Pearl Harbour." The Royal Navy's supremacy in the Pacific had secured an empire that stretched from Hong kong to New zealand." Now Japan was supreme and we were weak and naked." Sinking of the two ships on 10th December was stated to be the cause of Churchill's heart attack on 26th December in America. His physician Dr. Moran was requested to keep the news of his heart attack secret till his death. Dr. Moran kept his world till Churchill's death in 1965.

Nowhere the empire was more naked than in Malaya where Japanese units were landing. On 15 th February 1942, Japanese forces captured Britain's prized possession : Singapore. More humiliating than capturing Singapore was the surrender of an army of 85000 men under General Arthur Percival before a small army of 6000 Japanese soldiers. How 6000 Japanese soldiers captured

Singapore in just one month has not been described adequately in any book on 2nd World War and remains a mystery for an inquisitive reader till today. The demoralised soldiers composed the following quatrain that mocked Churchill's own words in praise of Air Force piolets.

Never before have so many
been buggered by so few
And neither the few nor the many
Have bugger all idea what to do

Churchill admitted in private that it was the worst disaster of British arms. One British army officer simply told his men,"Now you belong to Japanese army." Now Burma was the next to collapse. Rangoon was captured on 7th March and Burma came under the Japanese occupation on 27th March. A Burmese politician Ma Baw was made the Prime Minister. Now Japan was at Indian borders.

Now reputation of Churchill and England was at the lowest ebb for two reasons. Firstly that militarily, England was supposed to be a superpower. But it was now proved that its formation was as brittle as any army could be. In fact, Churchill was fighting the war with the armies of other countries and he was only a loquacious bully At the end of the war, casualties of British soldiers were not much as compared to others. Secondly, Indians in Asian countries started to flee out of panic to reach India. Likewise all the families of Britishers working in these countries like doctors, engineers, teachers etc also started fleeing. British authorities made all possible arrangements for safe evacuation of these families but did absolutely nothing to help the Indians. They had to walk on foot hundreds of miles to reach Imphal or other places through very thick hilly jungles. So lakhs of people died in the way due hunger, thrust and malarial diseases. This fact greatly impacted the psychology of Gandhi Ji. He felt that if Japan attacked India, the Britishers would flee to Egypt or England and leave Indians to the mercy of Japanese army. He also opined that Japan would attack India simply because India was under the British rule otherwise Japan had no enmity with India. This was the main reason for his launching the Quit India Movement in August 1942.

The war that looked so far away was now at the Indian border. Gandhi Ji started sermonising that the onslaught of Japanese would be born with nonviolent means. Nehru also started making some impractical observations. The persons who were really concerned were Chiang-Kai- Sheik, the Chinese head, President Roosevelt, Lord Attlee and General Claude Auchinleck , Commander of British forces in Egypt. The question bothering their minds was would Indians fight if Japan attacked India. They felt that Indians in general already had sympathies with Germany because of step motherly treatment given to Congress and practising 'Divide and Rule' policy in naked form and giving upper hand to Jinnha everywhere. They also felt cheated when provincial ministries had to resign. So if Japan attacked India, Indians might rise against Britishers. Chiang -Kai- Sheik visited India and met Gandhi Ji for four hours without reaching any agreement. But he could sense that British army in India was unprepared to stop the Japanese Juggernaut. Also if Japanese came to know about political dissentions and anti -British sentiment in the minds of most Indians, then they would be tempted to invade and overrun India soon. He gave his assessment both to Churchill and Roosevelt. Claude Auchinleck told Churchill," India is vital to our existence. We could still hold India without the Middle East but we cannot hold Middle East without India." Roosevelt was worried that if Burma-China road remained under Japanese occupation for long, then China would be doomed. Lord Attlee who was number two in the cabinet, told Cabinet on 2nd February (before Singapore fell) ," Now is the time for showing statesmanship. A renewed effort be made to get the leaders of major political parties to unite and both Amery and Linlithgow were not the men of the hour." T.B.Sapru and 12 other liberals that whole of India would be on England's side if India was given Dominion Status like Australia followed by formation of a national Government. The editor of American magazine 'Foreign Affairs ' wrote that India had become the touchstone of of the Anglo-American alliance. Finally Attlee cut the Gordian knot when he submitted a memorandum to the Cabinet which suggested," A single representative from the cabinet should be sent to India with full powers to negotiate a final settlement with all major political parties.There is a precedent for such action. Lord Durham saved Canada to the British Empire. We need a man to do in India what Durham did in Canada in 1838." Any suggestion to Churchill to give concessions to India was like showing a red rag to a bull. But now Churchill's hand had gone weak after the fall of Singapore and he was constrained to agree to the memorandum submitted by Attlee. Churchill offered to go himself but the doctors dissuaded him to take a long journey because of unhealthy condition of his heart. Finally Sir Stafford Cripps, who was Leader of the House of Commons and a Labour stalwart was chosen for the visit. He was socialist like Nehru and vegetarian like Gandhi Ji. He had excellent relations with Nehru and had also met Jinnha in December 1939. .

After having detailed discussions with Churchill, Cripps left England on 15th March 1942 and reached India on 22nd. He came with a premeditated proposal, called Cripps Offer, and discussed first with Gandhi Ji and then with other leaders. The proposal was in five parts.

I. Full Dominion status to India after the war with a right to secede from the Commonwealth.

2. A post war Constituent Assembly to frame the Constitution. The provincial governments to send their elected members in the Assembly.

3. A national government composed of leaders of leading political parties to be formed now to run the administration.

4. Princes would have the right to nominate their representatives to sit in the Constituent Assembly to decide the future of their states.

5. At the end of the war, every province would have the right to stay out and become a Dominion of equal status.

Cripps Offer had cofusion, loopholes and loose ends in ample. However, the Offer suggested that Constituent Assembly would frame the Constitution within the above guidelines. The points of dispute and friction are given below.

I. The Cripps Offer did not talk of independence. But a Dominion staying out of Commonwealth meant independence. Thus a province could also become an independent country.

2. It is not clear if it was binding on princes to remain in the federation.

3. There were 565 states and 565 princes. 50% were tiny states. Their geographical area was less than 50 square kms. Some states had areas less than 20 square kms.These states were not economically viable. These states needed to be merged into bigger states. How these States would send their representatives to the Constituent Assembly was not defined.

4. People in the states were living like slaves. Exploitation and poverty was omnipresent. 90% princes were leading profligate lives. The proposal did not talk of giving democratic rights to the people of the states.

5. There was no guideline to indicate the level of devolution of powers between the Viceroy and the National Government.

6. It appears that National Government would have control over provincial India only.

These points finally became the bones of contention during the meetings of Cripps with Congress leaders and finally led to the failure of the Cripps Mission.

शेष अगले भाग में

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB August 94) 26/5'3" B.Tech. from Punjab University. Working in I. T. Banglore with Rs. 19 lakh package PA. Father ASI in Chandigarh Police. Avoid Gotras: Sihag, Lathar, Redhu, Nadde. Cont.: 9417862853
- SM4 Jat Girl 26/5'5" B.Tech. (C.S.). Working as Senior Software Developer in Coforge Ltd. Noida with Rs. 10 lakh package PA. Father working in AFT Chandigarh. Mother home maker. Brother Army Officer (NDA). Avoid Gotras: Goyat, Khatkar, Nain. Cont.: 8427737450, 7988624647
- SM4 Jat Girl 26/5'4" PGDM in Finance, MBA. Working as Business Analyst at Gurgaon with Rs. 12 lakh package PA. Father businessman. Mother home maker. Avoid Gotras:Sheokand, Khatkar, Punia. Cont.: 9417366183
- SM4 Jat Girl (DOB March,92) 29/5'6". Working as Assistant Manager in Overseas Bank. Father retired Hony. Indian Army Captain. Avoid Gotras:Gawariya, Sangwan, Sunda. Cont.: 9646519210.
- SM4 Jat Girl 25/5'11". M.A. economics, B.Ed. Employed as teacher in Satluj Public School Panchkula. Family settled in Baltana (Pb.) Avoid Gotras: Dalal, Kadyan. Cont.: 8054064580
- SM4 Jat Girl 29/5'4". B.A. from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal University Rohtak. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 9354839881
- SM4 Jat Girl (DOB 07.10.95) 25/5'3" B.Sc, M.Sc, Doing B.Ed from Punjabi University. Family settled at Mohali. Avoid Gotras: Tomar, Dhama. Cont.: 9216551398
- SM4 Jat Girl (DOB 23.01.92) 29/5'4" BBA, MBA from M. D. University Rohtak. Avoid Gotras: Pawar, Ahlawat, Kadyan. Cont.: 9990447004
- SM4 Jat Boy (DOB 01.03.93) 28/6'1", B.A. LLB, LLM. Advocate in Punjab & Haryana High Court. Father Class-I officer (Rtd.) from Haryana government. Mother M.A. B.E.d house maker. Brother married & settled in Canada. Family settled in Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Jhanjharia. Cont.: 9876155702
- SM4 Jat Boy 28/5'10" B.Tech. (CSE) Employed in I.T. Company, Chandigarh. Avoid Gotras: Dalal, Kadyan. Family settled in Baltana (Punjab) Cont.: 8054064580
- SM4 Jat Boy (DOB 06.08.91) 29/5'6", B. Tech. (ECE) Working as Senior System Engineer in MNC Chandigarh with Rs. 14 lakh package PA. Father retired from Government service. Own house & plot at Panchkula. Preferred match working in MNC and urban living family girl. Avoid Gotras: Dahiya, Ruhil, Cont.: 9467806085, 7206328529
- SM4 Jat Boy (DOB 12.01.96) 25/5'9", Degree in International Marine Diver. Working as Diver in ONGC with package of Rs. 15 lakh PA. Father Sub. Inspector in Chandigarh Police, mother housewife. Single child. Family settled at Chandigarh. Avoid Gotras: Jhajhria, Bhambu, Mahla, Baloda. Cont.: 9501954042
- SM4 Jat Boy (DOB 28.10.91)29/5'10", B.Tech. from PEC Chandigarh. Working as Software Engineer in Banglore with package Rs. 13 lakh PA. Family settled in Zirakpur. Avoid Gotras: Kajla, Gawaria, Siwach, Khiyalia. Cont.: 9041149778
- SM4 Jat Boy (DOB March 92) 28/5'9" B.S.c (Computer Science) from Punjab University. Pursuing MCA. Employed in Kurukshetra University Kurukshetra as Clerk on regular basis. Father in private job. Mother housewife. Sister married and employed in Punjab Government. Family settled in Mohali. Preferred match in Government job. Avoid Gotras: Jadge, Budhrain. Cont.: 9056787532.
- SM4 Jat Boy26/6'1"Polytechnic Electric Diploma.Working in MNC with package of Rs. 4 lakh PA. Mother retired teacher. Brother, sister well settled. Preferred tall girl in service.Avoid Gotras: Mor, Malik, Budhwar Cont.: 8295865543
- SM4 Jat Boy(DOB 26.05.94) 26/6'4"B.Tech.Mechanical Degree Auto Cat.Settled in Canada (Toronto). Father in Haryana Govt. Mother school teacher in Haryana Govt. Avoid Gotras: Sayan, Punia Cont.: 9416877531, 9417303417
- SM4 Divorcee Jat Boy (DOB11.05.81) 39/5'11"MBA (IT). Working in HCL Noida as Network Consultant. Preferred Tri-city/NCR match. Avoid Gotras: Deswal, Dahiya. Cont.: 9466629799, 9255525099
- SM4 Jat Boy(DOB17.12.95) 25/6'1" Employed as Nursing officer in ESIC Hospital, Govt. of India in U.P. with salary of Rs. 82000/- PM. Preferred BDS, BAMS or employed match. Avoid Gotras: Bhanwala, Mann, Khatkar. Cont.: 9417579207
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89)31/5'10" B.Tech.in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA.Father businessman.Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड़िग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड़िंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और पानी के कनैक्शन के लिये भी सरकारी कोष से फंड मंजूर हो गया है और शीघ्र ही पानी की आपूर्ति का कनैक्शन चालू हो जायेगा।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : 0172–2654932 2641127

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोसियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।